सच्चाई के दम पर जोश के साथ...

RNI No: UPHIN/2023/86769

www.swarajindianews.com

swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews

मूल्यः ₹ 02

स्वराज इंडिया

सांध्यकालीन समाचार पत्र

कानपुर, मंगलवार, 17 जून, 2025
वर्षः 02, अंकः 167, पृष्ठः 8+4

योगी सरकार की डैशबोर्ड रैंकिंग में छाए रहे तेज-तर्रार टॉप 10 आईएएस

» Pg 12

इनसाइड डीएम के साथ जनता, सीएमओ के साथ राजनेता... » Pg 03

2027 विस चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ लड़ेंग

यूपी : अखिलेश यादव ने कर दिया ऐलान

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक बार फिर 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी रणनीति स्पष्ट कर दी है। लखनऊ में आयोजित प्रेस वार्ता में अखिलेश ने ऐलान किया कि वह इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। इससे पहले यूपी दौरे पर आए कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कहा था कि कांग्रेस गठबंधन सहयोगी के साथ विधानसभा चुनाव लड़ेगी।

अखिलेश यादव ने कहा कि सपा 2027 का विधानसभा चुनाव इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर लड़ेगी। उनके इस बयान से गठबंधन में एकजुटता का संदेश गया है। साथ ही, यह आने वाले चुनावी समीकरणों को लेकर भी एक संकेत है। अखिलेश यादव ने कानपुर के सीएमओ के तबादले को लेकर योगी सरकार पर कटाक्ष किया। उन्होंने सरकार के कामकाज पर सवाल उठाए।

कोयले का घोल पिलाया जा रहा : अखिलेश यादव ने राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि मरीजों को दवा के नाम पर कोयले का घोल पिलाया जा रहा है और गलत इंजेक्शन से मौतें हो रही हैं। सपा मुखिया ने बुनकरों की स्थिति पर भी चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि बुनकरों को आधुनिक सुविधाएं मिलनी चाहिए। मुख्यमंत्री को बुनकरों की समस्याओं की समझ नहीं है।

डबल इंजन की सरकार के डिब्बे टकरा रहे : अखिलेश

उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर निशाना साधते हुए कहा कि प्रदेश में दूग्ध उत्पादन नहीं हो रहा है और सरकार भी इसकी मदद बंद कर रही है। सरकार काउ मिल्क प्लांट भी बंद कर चुकी है।

उन्होंने कहा कि बुनकरों की कमाई का बड़ा हिस्सा बिचौलियों के पास चला जाता है। उनके पास काम करने के लिए पूंजी नहीं बचती है। हालत यह हो गई है कि बुनकरों के लिए बनाए कपड़ों के लिए अब कोई खरीददार नहीं मिलता है। अखिलेश ने राज्य सरकार से अलग से योजना चलाने की मांग करते हुए कहा कि इन लोगों की आर्थिक समस्या का समाधान करने के लिए सरकार को अलग तरह योजनाएं चलानी पड़ेगी। प्रदेश में बिजली की बढ़ती कीमतों पर निशाना साधते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में बिजली मंहगी करने की तैयारी चल रही है। प्रदेश में पहले से ही मंहगाई बढ़ रही है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि अगर संकट आया तो हम लोग मोबाइल कैसे चार्ज करेंगे। प्रदेश सरकार के अंदर जारी टशन को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार के डिब्बे टकरा रहे हैं। कौशांबी में दोनों डिप्टी सीएम माहौल खराब कर रहे हैं। पीडीए के लोगों को न्याय नहीं मिल रहा है।

यूपी में सोने के दम पर अच्छे दिन लाएगी सपा!

10 दिन में 3 बड़े ऐलान, क्या है रणनीति?

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश में वर्ष 2027 के लिए सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी ओर से अभी से तैयारी शुरू कर चुके हैं। कहीं नए वादों की बौछार है तो कहीं तो वहीं इन वादों पर वादाखिलाफी के दावे किए जा रहे हैं। सपा चीफने 10 दिन में तीन बड़े ऐलान किया है। कुछ ऐसा ही अब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और राज्य सरकार में उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच हो रही है।

दरअसल, सपा चीफ बीते करीब दो हफ्तों में विभिन्न मौकों पर समाज के अलग-अलग नायकों की सोने की प्रतिमाएं लगाने का वादा कर चुके हैं। अब इसी क्रम में उन्होंने रविवार को कहा है कि सपा की सरकार आएगी तो कन्नौज में सम्राट हर्षवर्धन की सोने की प्रतिमा लगाई जाएगी। रविवार को अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे अखिलेश ने कहा कि हम लोग जब सरकार में आएंगे तो कन्नौज का जिनका इतिहास है सम्राट हर्षवर्धन जी, उनकी सोने की प्रतिमा लगाई जाएगी। उनका यह ऐलान उस वक्त आया है जब कन्नौज में एक चौराहे का नाम अहिल्याबाई होल्कर के नाम

पर किए जाने का ऐलान किया गया है।

क्या है सपा की रणनीति? : इसके अलावा जब बीते दिनों उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव की कांस्य प्रतिमा का अनवारण किया तब अखिलेश यादव ने एक प्रेसवाताऽ में कहा कि राज्य में जब उनकी सरकार आएगी तब लखनऊ में गोमती रिवर फ्रंट पर महाराजा सुहेलदेव की सोने की प्रतिमा लगाई जाएगी। इससे पहले 6 जून को सपा चीफने यह भी कहा कि शिवाजी महाराज के सम्मान में आगरा में एक भव्य संग्रहालय बनाया जाएगा और लखनऊ में गोमती नदी के तट पर सिंहासन पर बैठी उनकी एक प्रतिमा स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि सिंहासन सोने से बना होगा।

क्या बोले केशव ?

अब अखिलेश के इन वादों में से एक पर यूपी के डिप्टी सीएम केशव ने प्रतिक्रिया दी है। सोशल मीडिया साइट एक्स पर केशव ने लिखा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की सरकार ने 2025 में लोकमाता अहिल्याबाई होल्कर जी की 300वीं जयंती ऐतिहासिक गरिमा के साथ मनाई – तभी नींद से जागे सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव! अब 2027 विधानसभा चुनाव निकट देखकर 'सोने की मूर्ति' का झुनझुना बजा रहे हैं। 2012-17 में सीएम थे, तब दलितों-पिछड़ों के महापुरुषों का अपमान किया तब इनकी याद क्यों नहीं आई। अब जब 2047 तक सत्ता सपने जैसी लग रही है, तो जुमलों से जनता को गुमराह कर रहे हो। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि अखिलेश यादव, सोने के दम पर यूपी में सपा के अच्छे दिन ला पाएंगे या नहीं।

भदोही में बड़ा हादसा

हाईटेंशन तार टूटा, पूरे गांव में दौड़ गया करंट छह लोग झुलसे

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

भदोही। भदोही जिले की कोतवाली क्षेत्र के हैबतपुर गांव में मंगलवार को अचानक हाईटेंशन तार गिरने से छह लोग गंभीर रूप से झुलस गए। तार टूटकर ट्रांसफार्मर पर गिरा। जिससे पूरे गांव में बिजली का करंट दौड़ गया, जो जहां था, वहीं करंट की चपेट में आ गया। घटना से पूरे गांव के इलेक्ट्रानिक उपकरण ध्वस्त हो गए। घायलों का औराई सीएचसी में उपचार चल रहा है। जिसमें कई की स्थिति गंभीर बताई जा रही है। घटना के बाद हैबतपुर समेत आसपास की बिजली काट दी गई है। लोगों ने बिजली विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया।

बिहार, बंगाल समेत 5 राज्यों में बिगड़ेगा मौसम!

भीषण गर्मी के बीच अगले 24 घंटे में तेज आंधी-बारिश का डबल अटैक

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

नई दिल्ली। देश में भीषण गर्मी से राहत मिलने की उम्मीद है क्योंकि मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, बिहार और झारखंड में भारी बारिश की संभावना जताई है।

देश में भीषण गर्मी के बीच मौसम विभाग ने खुशखबरी दी है। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में गुजरात के सौराष्ट्र और कच्छ क्षेत्र, पश्चिम बंगाल के मैदानी इलाके, ओडिशा, बिहार और झारखंड में तेज आंधी और बिजली के साथ भारी से बहुत भारी बारिश होने की संभावना है। वहीं उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां 18 जून से भारी बारिश होने की संभावना है।

यूपी में बारिश कब होगी : उत्तर प्रदेश में 18 जून से मानसून दस्तक दे देगा। मौसम विभाग के मुताबिक 19 और 20 जून को यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है।

इस दौरान बादल गरजने एवं बिजली चमकने के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इस दौरान राजधानी लखनऊ और नोएडा-गाजियाबाद में भी बारिश की संभावना जताई गई है।

उत्तर प्रदेश में कब हो सकती है बारिश

उत्तर प्रदेश में 18 जून से मानसून दस्तक दे देगा। मौसम विभाग के मुताबिक 19 और 20 जून को यूपी के कई जिलों में मूसलाधार बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इस दौरान बादल गरजने एवं बिजली चमकने के साथ ही 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चल सकती है। इस दौरान राजधानी लखनऊ और नोएडा-गाजियाबाद में भी बारिश की संभावना जताई गई है।

सीएमओ डीएम प्रकरण से सतह पर आई भाजपा की गुटबाजी

सीएमओ प्रकरण से एक बार फिर उजागर हुई भाजपा में गुटबाजी की लाइलाज बीमारी

- सीएमओ का चिट्ठी वाला दांव पड़ा उल्टा
- सीएमओ के विरोध में दो विधायकों ने सीधे मुख्यमंत्री को लिखी चिट्ठी
- सीएमओ का आचरण सेवा नियमावली का उल्लंघन भी है

निर्मल तिवारी/ स्वराज इंडिया

कानपुर। ऐसा लग रहा है जिलाधिकारी कानपुर नगर द्वारा लगातार कसी जा रही नकेल से आजिज सीएमओ कानपुर नगर ने कई जगह अपना दुखड़ा रोया। जिसके दो परिणाम सामने आए। दुखड़ा सुन रहे कुछ चतुर सुजानों ने जहां उनका आडियो वायरल कर दिया वहीं कुछ माननीय उनका दुखड़ा सुन पसीज गए और सीएमओ साहब के पक्ष में चिट्ठी लिख दी। सबसे पहले विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की चिट्ठी सामने आई। उसके बाद एमएलसी अरुण पाठक और गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मैथानी की सीएमओ के पक्ष में शासन को लिखित चिट्ठी चर्चा का विषय रही। आम कनपुरियों के बीच जब सीएमओ के राजनीतिक सपोर्ट की चर्चा चल रही थी, उसी बीच शाम होते-होते बिठूर विधायक अभिजीत सिंह सांगा की सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखित चिट्ठी सामने आ गई। जिसमें माननीय विधायक ने सीएमओ के भ्रष्टाचार की पोल खोल कर रख दी। इतना ही नहीं देर रात तक किदवई नगर विधायक महेश त्रिवेदी की सीएम को लिखित चिट्ठी मीडिया जगत में वायरल हो गई जिसका लब्बोलुआब सीएमओ साहब के आचरण की जांच की संस्तुति जैसा है। अब शहर में आम हो या खास सबके बीच चर्चा का एक ही विषय है कि ऐसा क्या कारण है कि कानपुर के कुछ माननीय की निगाह में सीएमओ बहुत अच्छे हैं वहीं कुछ की निगाह में सीएमओ का आचरण बहुत ही खराब है।

विशुद्ध प्रशासनिक मामले में राजनीतिज्ञों का क्या काम

विषय ऐसा है नहीं कि राजनीति या राजनीतिज्ञ की एंट्री नजर आए। मामला खालिस प्रशासनिक व्यवस्था का है। जिलाधीश, जो जिले का मुखिया है, नागरिक प्रशासन का कप्तान है, लीडर है, वह सरकार और शासन की मंशानुरूप व्यवस्थाओं के सुचारू संचालन हेतु पर्यवेक्षण कर रहा है व औचक निरीक्षण कर रहा है?। कहा जा सकता है व्यवस्थाओं को चाक चौबंद करने के लिए प्रयत्नशील है। ऐसा जिलाधिकारी जिसकी कार्यशैली से जनता बहुत खुश है, जो आमजन मे ये आस बांध रहा है कि सरकार को सब की चिंता है और सरकार सब की बेहतरी के लिए कार्य कर रही है। सबसे बड़ी बात है जिलाधिकारी की कार्यशैली, जो संदेश देती है कि इस सरकार की नीति भ्रष्टाचार कदाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की है। ऐसे जिलाधिकारी के

जिले के सत्ता पक्ष के जन प्रतिनिधियों को तो उनके इस व्यवहार से अनुग्रहीत होना चाहिए, जिलाधिकारी से प्रसन्न रहना चाहिए और जरूरत पड़ने पर ऐसे अधिकारी का संबल बनना चाहिए। लेकिन कानपुर में राजनीति की गंगा उल्टी बह रही है। वैसे भी कानपुर की बात ही निराली है और उससे भी ज्यादा निराले हैं कानपुर के सत्ता पक्ष के कुछ जनप्रतिनिधि जिन्होंने कानपुर की शिक्षा स्वास्थ्य व अन्य बेपटरी नागरिक व्यवस्थाओं को पटरी पर लाने का प्रयास कर रहे जिलाधिकारी जितेन्द्र प्रताप सिंह के विरुद्ध ही ऐसा मोर्चा सा खोल दिया है। कानपुर की जनता जनार्दन कह रही है नेताजी अपने तो कमाल कर दिया। आप तो जानते ही हैं बात जब कानपुर की होती है तो तमाम विशेषताओं से पहले जिक्र आता है ठग्गू के लड्डू का और आजकल कनपुरिए सीएमओ प्रकरण पर अपने माननीयों के लिए यही पंक्ति दोहराते नजर आ रहे हैं ऐसा कोई सगा नहीं जिसे हमने ठगा नहीं।

कानपुर के जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह को कानपुर का चार्ज संभाले अभी 5 महीने ही हुए हैं। इन पांच महीनों में उनकी कार्यशैली ने शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्र में खलबली मचा दी है ।शिक्षा क्षेत्र के महारथी तो मौन हैं लेकिन स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े महारथियों को ऐसा प्रतीत हो रहा है ज्यादा ही चोट पहुंची है। जाने अनजाने में सत्ता पक्ष के कुछ माननीय भी इन चैटिल लोगों के हमदर्द बने नजर आ रहे हैं ।

सीएमओ के पेंच कसे गए तो सामने आए हमदर्द

कानपुर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह की कार्यशैली कुछ ऐसी है कि लगातार वह विभिन्न विभागों, कार्यालयों का निरीक्षण करते रहते हैं। अधिकांशतः यह निरीक्षण औचक होते हैं। बिना बताए होने वाले इन निरीक्षणों से अक्सर ही नागरिक प्रशासन की पोल खुलती रहती है। स्वास्थ्य महकमा भी इससे अछूता नहीं है। सरकार और शासन के अव्वल वरीयता वाले इस विभाग में डीएम कानपुर नगर के हर बार निरीक्षण में कमियां सामने आईं। जिससे यह संदेश निकला कि यह विभाग अपनी लकीर पर ही चलता है। निरीक्षण लिखा-पढ़ी आदि का इस पर कोई विशेष फर्क पड़ता नहीं है।

18 जनवरी को जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार संभालने के अगले दिन ही डीएम साहब नवाबगंज पीएचसी का औचक निरीक्षण करते हैं जहां डॉक्टर सहित आठ अन्य लोग उन्हें नदारत मिलते हैं। तब से अब तक 8 से 9 मौकों पर डीएम कानपुर नगर ने विभिन्न सीएचसी, पीएचसी, अस्पतालों और कार्यालय का निरीक्षण किया और हर बार अनियमितताएं पकड़ीं। हद तो तब हो गई जब 4 फरवरी को सीएमओ कानपुर नगर के कार्यालय का डीएम द्वारा निरीक्षण किया गया। इस निरीक्षण में सीएमओ सहित 34 कर्मचारी कार्यालय से अनुपस्थित मिले।

सीएमओ की कार्यकुशलता और कर्त्तव्यपरायणता के उदाहरण!

भाजपा के माननीय जिन्हें कार्य कुशल बता रहे हैं वह सीएमओ कानपुर नगर डॉक्टर हरिदत्त नेमी औचक निरीक्षण के समय कार्यालय से बिना किसी कारण अनुपस्थित थे। इतना ही नहीं जब 4 मार्च को जिला अस्पताल उर्सला का डीएम ने औचक निरीक्षण किया तो वहां पर भी अनियमितताएं मिलीं और शासन द्वारा निर्देशित किए जाने के बाद भी यही कार्य कुशल, जनता के हमदर्द सीएमओ साहब ओपीडी में मरीज नहीं देख रहे थे और ना ही इनके प्रशासनिक मातहत चिकित्सक ओपीडी में मरीज देख रहे थे। भाजपा के कई माननीय जिन सीएमओ की कार्यशैली और कर्तव्यनिष्ठा से बहुत अधिक खुश हैं उन्हीं सीएमओ कानपुर नगर की नाक के नीचे कांशीराम अस्पताल में पिछले महीने की 25 तारीख को जब डीएम कानपुर नगर पहुंचे तो 64 कर्मचारी गायब मिले। बिरहाना रोड केपीएम की डॉक्टर दीप्ति तो याद ही होंगी जो रजिस्टर में एक दो नहीं 25 फर्जी मरीजों का नाम लिखकर उनका इलाज कर रही थीं और उन्हें मुफ्त दवा भी दे रही थीं।आश्चर्य की बात है कानपुर की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में इतना अधिक गड़बड़झाला सामने आने के बाद भी कुछ माननीय सीएमओ के पक्ष में चिट्ठी लिख रहे हैं, उन्हें कर्तव्यपरायण और कार्य कुशल बता रहे हैं।

कुल मिलाकर सीएमओ कानपुर नगर के लिए कानपुर का यह कार्यकाल उनकी सर्विस का सबसे बुरा दौर साबित होने जा रहा है। कहा जाता है सोशल मीडिया का उपयोग दोधारी तलवार की तरह होता है। यदि आपसे जरा सी चूक हुई तो आप खुद भी चोटिल हो सकते हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है डीएम कानपुर नगर सोशल मीडिया के सिद्धहस्त हैं। वो इस प्लेटफार्म का अच्छे से उपयोग करना जानते हैं?। लगभग सभी निरीक्षण के बाद वह आउटपुट्स को सोशल मीडिया पर अपलोड करते हैं। शायद इसी से प्रेरित होकर सीएमओ साहब ने भी अपनी बात सोशल मीडिया पर रखने का प्रयास किया। जिसमें सिफारिशी चिट्ठियों को वायरल करना भी शामिल है। लेकिन ऐसा लग रहा है सीएमओ साहब इसमें बुरी तरह गच्चा खा गए।जिसका सबसे बड़ा कारण आम जनमानस को उनके स्वास्थ्य विभाग और सेवाओं से नकारात्मक अनुभव मिलना है। वहीं डीएम कानपुर नगर को कनपुरिए हीरो की नजर से देख रहे हैं। कुछ माननीयों ने भले ही कतिपय कारणों से सीएमओ कानपुर नगर के पक्ष में चिट्ठी लिख दी हो लेकिन जनता जनार्दन डीएम के पक्ष में है?। इसके साक्षात प्रमाण सोशल मीडिया पर डीएम के पक्ष में चल रहे कैम्पेन के रूप में उपलब्ध हैं।

डीएम के साथ जनता, सीएमओ के साथ राजनेता

» कानपुर में छिडे प्रशासनिक संग्राम के बीच पक्ष और विपक्ष का माहौल बना दिया गया

» बीजेपी नेता आधे धडों में बंटे दिख रहे हैं

» सीएमओ के पक्ष में कुछ विधायकों ने पत्र भेजे तो जनता डीएम के साथ खड़ी है

प्रमुख संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। महानगर कानपुर में डीएम बनाम सीएमओ के विवाद में जनप्रतिनिधियों के कूदने से मामला और गहरा गया है। कई बीजेपी विधायकों ने सीएमओ का पक्ष लेकर शासन को पत्र भेजे हैं तो वहीं डीएम के साथ जनता खडी नजर आ रही है। वहीं, किदवईनगर से विधायक महेश त्रिवेदी और बिठूर से विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने डीएम के कार्यों की तारीफ करते हुए पत्र मुख्यमंत्री को भेजा है। वहीं, अबतक इस प्रकरण में शासन चुप्पी साधे हुए हैं, स्वास्थ्य मंत्री बृजेश पाठक का भी कोई रिएक्शन नहीं आया है। इससे प्रशासनिक माहौल और खराब होता जा रहा है।

डीएम और सीएमओ प्रकरण सोशल मीडिया में छाया हुआ है। अधिकतर जनता डीएम के पक्ष में खडी नजर आ रही है, कई सोशल मीडिया यूजरों का कहना है कि अरसे बाद कानपुर को अच्छा और लोकप्रिय डीएम मिला है। डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ने जनसुनवाई में बेहतर कार्य किया। स्वास्थ्य और शिक्षा पर ध्यान देते हुए लगातार चाबुक चलाया तो हडकंप मचा। हकीकत यह है कि जिले के सीएचएसी और पीएचसी रेफर सेंटर बनकर रह गए हैं। कई जगह तो डॉक्टर नहीं मिलते हैं अगर मिल भी गए तो सही उपचार नहीं मिलता है। वहीं, शहर में निजी अस्पतालों की भरमार है, जिनके पास न तो प्रशिक्षित कर्मी हैं और न ही अन्य सुरक्षा के कोई ठोस इंतजाम।

अल्टीमेटली स्वास्थ्य विभाग के मुखिया सीएमओ डा0 हरिदत्त नेमी पर सवाल उठ लाजिमी हैं, डीएम ने शासन को पत्र लिखा तो जनप्रतिनिधियों का सुरक्षा कवच लेकर सीएमओ अपने को पाक साफ बताने की कोशिश कर रहे हैं। वहीं, सीएमओ का आरोप है कि एक दागी ठेकेदार का पेमेंट करवाने का दबाव डीएम की ओर डाला जा रहा था,

इसलिए मुझे बदनाम किया गया। हालांकि, सीएमओ का तर्क गले नहीं उतरता है क्यों कि एक वायरल ऑडियो क्लिप में डीएम के लिए कहे गए आपत्तिजनक शब्द इस बात की गवाही दे रहे हैं कि सीएमओ की भडास कुछ और ही है।

अभिभावक महासंघ ने डीएम के लिए जारी किया पत्र

अखिल भारतीय अभिभावक संघ के अध्यक्ष राकेश मिश्रा निडर ने मुख्यमंत्री उप्र के नाम जारी किए पत्र में कहा कि डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह ईमानदार और साफ सुथरी छवि के अधिकारी हैं। तैनाती के बाद से ही उन्होने सरकारी महकमों को सुधारने के लिए ताबडतोड एक्शन लिए। जनसुनवाई में आने वालों को त्वरित न्याय दिलाने का काम कर रहे हैं। कुछ लोग पूर्वनियोजित ढंग से जितेंद्र प्रताप सिंह का यहां से हटाना चाह रहे हैं। पत्र में आगे लिखा है कि दुखद यह है कि बीजेपी के वरिष्ठ नेता महाना, अरूण पाठक, मैथानी सीएमओ का सहयोग कर रहे हैं, इसमें कहीं न कहीं कुछ दाल में काला है। क्यों कि जिस तरह से दक्षिण शहर में अबतक अस्पताल चालू नहीं हो सका और नेताओं ने इसपर कोई पहल नहीं की। यह भी बडी बात है।

नेमी ठेकेदारों से मांगते थे मोटा कमीशन!

सूत्रों का दावा है कि सीएमओ डा. हरिदत्त नेमी सिंडीकेट के आदमी हैं। यूपी में सरकारें बदली लेकिन राज्य के 36 जिले सिंडीकेट के इशारे पर आज भी चलते हैं।

इसमें एक पूर्व विधायक मुकेश श्रीवास्तव का नाम भी लिया जाता है कि वह किस तरह से स्वास्थ्य के बडे बडे ठेकों और सप्लाई के टेंडर जेम पोर्टल से अपने ठेकेदारों को दिलवाते देते हैं।

यह स्वास्थ्य विभाग के टॉप अफसरों में भी जगजाहिर है। दावा यहां तक है कि लखनउ में बैठे एक बडे अफसर भी बैक डोर से सिंडिकेट को बैकअप देते रहते हैं, इसी वजह से नेमी जैसे स्वास्थ्य अधिकारी डीएम से मोर्चा खोलने की ताकत रखते हैं।

हालांकि देखना यह है कि इस प्रकरण का अंजाम क्या होता है। 'स्वराज इंडिया' जल्द ही कुछ ठेकेदारों के मामलों का खुलासा करेगा जिसमें सीएमओ को कमीशन नहीं देने के कारण पेमेंट रोके गए हैं और शिकायतों को नजरअंदाज किया गया।

सपा विधायक ने कहा, यह लड़ाई सीएमओ और डीएम के बीच की नहीं

कानपुर से सपा के वरिष्ठ विधायक अमिताभ बाजपेई का भी बयान सामने आया है ।

उन्होंने कहा कि कानपुर में चल रही प्रशासनिक लड़ाई डीएम और सीएमओ के बीच की नहीं है, इसमें बड़े स्तर का खेल है। यह कहीं ना कहीं सरकार में चल रहे भ्रष्टाचार को उजागर करता है, लखनऊ स्तर की बात करें तो यह लड़ाई मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बीच की है जो जिसके पाले में है उसी हिसाब से पत्र जारी कर रहा है। कानपुर की जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है।

स्वराज इंडिया www.swarajindianews.com कानपुर सिटी कानपुर, सोमवार 16 जून, 2025 03

सीएमओ साहब तो बड़े वाले निकले...!

कानपुर डीएम और सीएमओ प्रशासनिक विवाद चरम पर पहुंचा

» सीएमओ के बचाव में विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने भेजी बचाव के लिए चिटठी

» डीएम ने स्वास्थ्य सेवाओं में मनमानी और लापरवाही को लेकर सीएमओ के खिलाफ शासन को भेजा था डीओ लेटर

मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर। डीएम कानपुर जितेंद्र प्रताप सिंह ने तैनाती के बाद से कई विभागों में दनादन निरीक्षण कर 'पानी' भर दिया। विभागों की खामियों को सुधारने के लिए पत्र भी जारी किए। डीएम की सख्ती की खबरें मीडिया में सुर्खियां लगातार बन रही थीं और जनता के बीच डीएम की लोकप्रियता भी देखी गई। डीएम ने जिले की स्वास्थ्य सेवाएं सुधारने के लिए कई बार औचक निरीक्षण किए और सीएमओ को कई कडे चेतावनी वाले पत्र भेजे। डीएम की सख्ती को लेकर सीएमओ रडार पर आ गए तो वह डीएम को सबक सिखाने के लिए मैदान में आ गए हैं।

बीते दिनों बताया जा रहा है कि एक सीएमओ की टेलीफोनिक बातचीत की रिकार्डिंग क्लिप वायरल हुई। इसमें डीएम के लिए सीएमओ द्वारा अपशब्द भाषा शैली के साथ कई बातें कही जा रही हैं। बात डीएम तक पहुंची तो उन्होने सीएमओ हरिदत नेमी को सीएम डैश बोर्ड की समीक्षा बैठक में खडा कर रिकार्डिंग को लेकर पूछा तो सीएमओ ने पल्लाझाडते हुए कह दिया कि मेरी रिकार्डिंग नहीं है, यह एआई से बनाई गई फर्जी क्लिप है। इससे नाराज डीएम ने कहा कि अगर फर्जी आडियो वायरल किया गया है तो एफआईआर करवानी चाहिए इसपर सीएमओ कुछ नहीं बोले, इसके बाद डीएम ने सीएमओ को मीटिंग से बाहर जाने को कह दिया। वहीं, डीएम ने प्रमुख सचिव स्वास्थ्य को पत्र लिखकर सीएमओ को हटाने के साथ विभागीय जांच करने के लिए कहा है। यह पत्र मीडिया में वायरल हुआ तो सीएमओ खुलकर मैदान में आ गए। उन्होने दावा किया है कि डीएम के द्वारा जानबूझकर टारगेट किया जा रहा है, दागी फार्मा कंपनी का 1.60 करोड रूपए का भुगतान करने का दबाव है, वहीं, डीएम को मेरे विभाग के कुछ लोगों के द्वारा गुमराह किया गया है इस प्रशासनिक घटनाक्रम की हलचल पूरे लखनउ सहित यूपी के कई जिलों में है। हालांकि, यह टकराव अब सत्ता के गलियारों तक पहुंच गया है। इसमें सीएमओ ने विक्टिम कार्ड खेलते हुए माहौल बनाना शुरू कर दिया है। कई नेताओं से लामबंदी करने में जुटे हुए हैं। देखना यह है कि इस लडाई में डीएम कानपुर जीतते या हैं सीएमओ, क्यों कि मामला काफी तूल पकड चुका है।

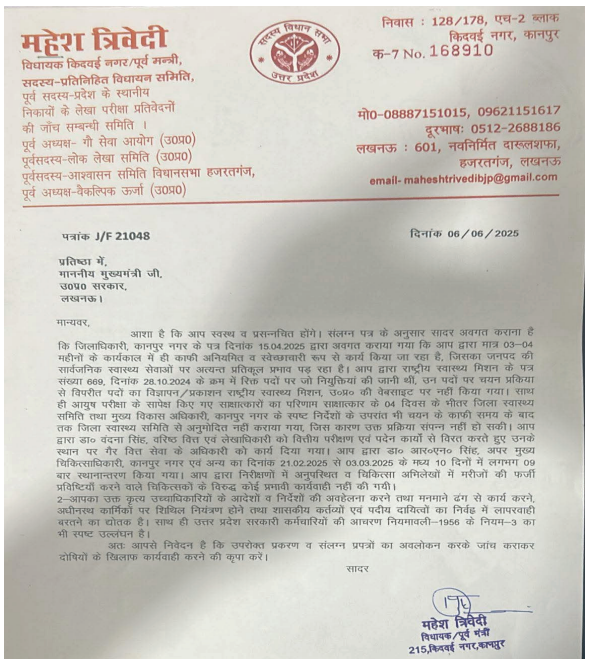

विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना का पत्र

एमएलसी अरुण पाठक का भी पत्र वायरल

सीएमओ डॉक्टर हरिदत्त नेमी का व्यवहार जनता के प्रति अच्छा रहा है एवं शासन के द्वारा स्वास्थ्य संबंधी जो भी योजनाएं चलाई जा रही हैं वो लगातार जनता के बीच पहुंच रही हैं कुछ इस तरह का लेटर पैड एमएलसी अरुण पाठक के लेटर पैड द्वारा वायरल हो रहा है।

सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह

सीएमओ के लिए सतीश महाना ले लगाया 'वीटो'

डीएम जितेंद्र प्रताप सिंह और सीएमओ हरिदत्त नेमी के बीच चल रहे विवाद में कानपुर के महाराजपुर विधानसभा से विधायक और वर्तमान में यूपी विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना की इंट्री हुई है। 11 जून 2025 को सतीश महाना की चिटठी डिप्टी सीएम बृजेश पाठक को संबोधित जारी की गई है। इसमें कहा गया है कि सीएमओ का कार्य व्यवहार जनता-जनप्रतिनिधि के प्रति मृदु और सराहनीय है, लगन के साथ काम करने वाला बताया। महाना ने डिप्टी सीएम से आग्रह किया है कि जनभावनाओं के आधार पर हरिदत्त नेमी को कानपुर से न हटाया जाए उन्हे यथावत रखा जाए। हालाकि, डीएम सीएमओ विवाद से पूर्व चिटठी जारी होना दिखाया गया है लेकिन हकीकत कुछ और भी हो सकती है। फिलहाल प्रकरण काफी चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरह से सीएमओ ने विधानसभा का वीटो कार्ड खेला है, इससे डीएम अलग-थलग पडते दिख रहे हैं। हालाकि, यह प्रशासनिक दृष्टिकोण से उचित नहीं लगता है।

स्वास्थ्य सेवाओं का बुरा हाल जगजाहिर

कानपुर के ग्रामीण इलाकों में बेहाल स्वास्थ्य सेवाएं जगजाहिर हैं। सीएचसी और पीएचसी में ग्रामीणों को उपचार नहीं मिलता है, डॉक्टर और कर्मचारी मनमाने ढंग से ड्यूटी करते हैं। कानपुर महानगर के अंदर तमाम नर्सिंग होम और अस्पताल खोल दिए गए, जिनमें सुरक्षा, स्वास्थ्य और अन्य इंतजाम नहीं है। इसपर डीएम ने लगाम कसने की कोशिश की। ऐसे में डीएम के द्वारा की सख्ती को सीएमओ ने दूसरे तरीके से ढाल बनाया। ऑडियो क्लिप में जिस तरह की 'ढोल बजाने वाला डीएम' जैसी शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है, इससे समझा जा सकता है कि सीएमओ किस कदर डीएम से खुन्नस खाए हैं। सीएमओ ने जिस तरह से बचने के लिए नेताओं की शरण ली है, इससे प्रशासनिक सिस्टम कमजोर जरूर होगा।

महेश त्रिवेदी
विधायक किदवई नगर/पूर्व मन्त्री,
सदस्य-प्रतिनिहित विधायन समिति,
पूर्व सदस्य-प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदनों की जाँच सम्बन्धी समिति ।
पूर्व अध्यक्ष- गौ सेवा आयोग (उ0प्र0)
पूर्वसदस्य-लोक लेखा समिति (उ0प्र0)
पूर्वसदस्य-आश्वासन समिति विधानसभा हजरतगंज,
पूर्व अध्यक्ष-वैकल्पिक ऊर्जा (उ0प्र0)

निवास : 128/178, एच-2 ब्लाक किदवई नगर, कानपुर
क-7 No. 168910
मो0-08887151015, 09621151617
दूरभाष: 0512-2688186
लखनऊ : 601, नवनिर्मित दारूलशफा, हजरतगंज, लखनऊ
email- maheshtrivedibjp@gmail.com

पत्रांक J/F 21048 दिनांक 06/06/2025

प्रतिष्ठा में,
माननीय मुख्यमंत्री जी,
उ0प्र0 सरकार,
लखनऊ।

मान्यवर,

आशा है कि आप स्वस्थ व प्रसन्नचित होंगे। संलग्न पत्र के अनुसार सादर अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, कानपुर नगर के पत्र दिनांक 15.04.2025 द्वारा अवगत कराया गया कि आप द्वारा मात्र 03-04 महीनों के कार्यकाल में ही काफी अनियमित व स्वेच्छाचारी रूप से कार्य किया जा रहा है, जिसका जनपद की सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। आप द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के पत्र संख्या 669, दिनांक 28.10.2024 के क्रम में रिक्त पदों पर जो नियुक्तियां की जानी थीं, उन पदों पर चयन प्रकिया से विपरीत पदों का विज्ञापन/प्रकाशन राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उ०प्र० की वेबसाइट पर नहीं किया गया। साथ ही आयुष परीक्षा के सापेक्ष किए गए साक्षात्कारों का परिणाम साक्षात्कार के 04 दिवस के भीतर जिला स्वास्थ्य समिति तथा मुख्य विकास अधिकारी, कानपुर नगर के स्पष्ट निर्देशों के उपरांत भी चयन के काफी समय के बाद तक जिला स्वास्थ्य समिति से अनुमोदित नहीं कराया गया, जिस कारण उक्त प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकी। आप द्वारा डा० वंदना सिंह, वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी को वित्तीय परीक्षण एवं पदेन कार्यो से विरत करते हुए उनके स्थान पर गैर वित्त सेवा के अधिकारी को कार्य दिया गया। आप द्वारा डा० आर०एन० सिंह, अपर मुख्य चिकित्साधिकारी, कानपुर नगर एवं अन्य का दिनांक 21.02.2025 से 03.03.2025 के मध्य 10 दिनों में लगभग 09 बार स्थानान्तरण किया गया। आप द्वारा निरीक्षणों में अनुपस्थित व चिकित्सा अभिलेखों में मरीजों की फर्जी प्रविष्टियाँ करने वाले चिकित्सकों के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की गयी।

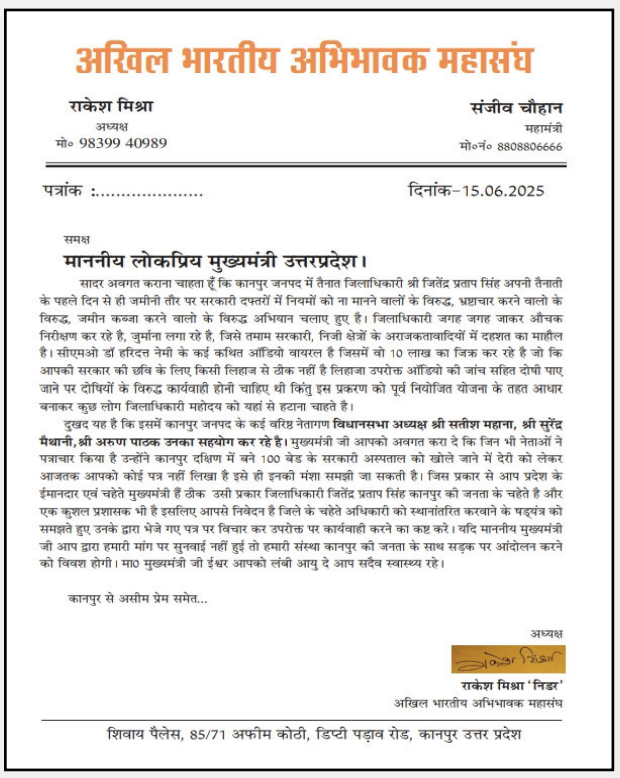

2-आपका उक्त कृत्य उच्चाधिकारियों के आदेशों व निर्देशों की अवहेलना करने तथा मनमाने ढंग से कार्य करने, अधीनस्थ कार्मिकों पर शिथिल नियंत्रण होने तथा शासकीय कर्तव्यों एवं पदीय दायित्वों का निर्वह्न में लापरवाही बरतने का द्योतक है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकारी कर्मचारियों की आचरण नियमावली-1956 के नियम-3 का भी स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः आपसे निवेदन है कि उपरोक्त प्रकरण व संलग्न प्रपत्रों का अवलोकन करके जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करने की कृपा करें।

सादर

महेश त्रिवेदी
विधायक/पूर्व मंत्री
215,किदवई नगर,कानपुर

डीएम सीएमओ विवाद में विधायक महेश त्रिवेदी की इंट्री,,, सीएमओ के खिलाफ खोला मोर्चा

अखिल भारतीय अभिभावक महासंघ

राकेश मिश्रा
अध्यक्ष
मो० 98399 40989

संजीव चौहान
महामंत्री
मो०नं० 8808806666

पत्रांक :.................... दिनांक-15.06.2025

समक्ष

माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री उत्तरप्रदेश।

सादर अवगत कराना चाहता हूँ कि कानपुर जनपद में तैनात जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह अपनी तैनाती के पहले दिन से ही जमीनी तौर पर सरकारी दफ्तरों में नियमों को ना मानने वालों के विरुद्ध, भ्रष्टाचार करने वालो के विरुद्ध, जमीन कब्जा करने वालो के विरुद्ध अभियान चलाए हुए है। जिलाधिकारी जगह जगह जाकर औचक निरीक्षण कर रहे है, जुर्माना लगा रहे है, जिसे तमाम सरकारी, निजी क्षेत्रों के अराजकतावादियों में दहशत का माहौल है। सीएमओ डॉ हरिदत्त नेमी के कई कथित ऑडियो वायरल है जिसमें वो 10 लाख का जिक्र कर रहे है जो कि आपकी सरकार की छवि के लिए किसी लिहाज से ठीक नहीं है लिहाजा उपरोक्त ऑडियो की जांच सहित दोषी पाए जाने पर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही होनी चाहिए थी किंतु इस प्रकरण को पूर्व नियोजित योजना के तहत आधार बनाकर कुछ लोग जिलाधिकारी महोदय को यहां से हटाना चाहते है।

दुखद यह है कि इसमें कानपुर जनपद के कई वरिष्ठ नेतागण **विधानसभा अध्यक्ष श्री सतीश महाना, श्री सुरेंद्र मैथानी, श्री अरुण पाठक उनका सहयोग कर रहे है।** मुख्यमंत्री जी आपको अवगत करा दे कि जिन भी नेताओं ने पत्राचार किया है उन्होंने कानपुर दक्षिण में बने 100 बेड के सरकारी अस्पताल को खोले जाने में देरी को लेकर आजतक आपको कोई पत्र नहीं लिखा है इसे ही इनकी मंशा समझी जा सकती है। जिस प्रकार से आप प्रदेश के ईमानदार एवं चहेते मुख्यमंत्री हैं ठीक उसी प्रकार जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह कानपुर की जनता के चहेते है और एक कुशल प्रशासक भी है इसलिए आपसे निवेदन है जिले के चहेते अधिकारी को स्थानांतरित करवाने के षड्यंत्र को समझते हुए उनके द्वारा भेजे गए पत्र पर विचार कर उपरोक्त पर कार्यवाही करने का कष्ट करे। यदि माननीय मुख्यमंत्री जी आप द्वारा हमारी मांग पर सुनवाई नहीं हुई तो हमारी संस्था कानपुर की जनता के साथ सड़क पर आंदोलन करने को विवश होगी। मा0 मुख्यमंत्री जी ईश्वर आपको लंबी आयु दे आप सदैव स्वास्थ्य रहे।

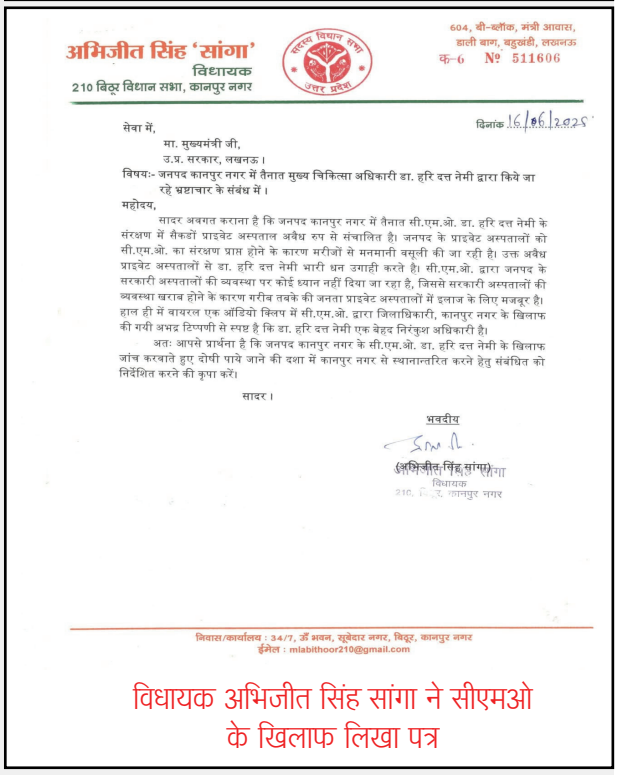

कानपुर से असीम प्रेम समेत...

अध्यक्ष

राकेश मिश्रा 'निडर'
अखिल भारतीय अभिभावक महासंघ

शिवाय पैलेस, 85/71 अफीम कोठी, डिप्टी पड़ाव रोड, कानपुर उत्तर प्रदेश

अभिजीत सिंह 'सांगा'
विधायक
210 बिठूर विधान सभा, कानपुर नगर

604, बी-ब्लॉक, मंत्री आवास, डाली बाग, बहुखंडी, लखनऊ
क-6 №. 511606

दिनांक 16/06/2025

सेवा में,
मा. मुख्यमंत्री जी,
उ.प्र. सरकार, लखनऊ।

विषयः- जनपद कानपुर नगर में तैनात मुख्य चिकित्सा अधिकारी डा. हरि दत्त नेमी द्वारा किये जा रहे भ्रष्टाचार के संबंध में।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि जनपद कानपुर नगर में तैनात सी.एम.ओ. डा. हरि दत्त नेमी के संरक्षण में सैकडों प्राइवेट अस्पताल अवैध रुप से संचालित है। जनपद के प्राइवेट अस्पतालों को सी.एम.ओ. का संरक्षण प्राप्त होने के कारण मरीजों से मनमानी वसूली की जा रही है। उक्त अवैध प्राइवेट अस्पतालों से डा. हरि दत्त नेमी भारी धन उगाही करते है। सी.एम.ओ. द्वारा जनपद के सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे सरकारी अस्पतालों की व्यवस्था खराब होने के कारण गरीब तबके की जनता प्राइवेट अस्पतालों में इलाज के लिए मजबूर है। हाल ही में वायरल एक ऑडियो क्लिप में सी.एम.ओ. द्वारा जिलाधिकारी, कानपुर नगर के खिलाफ की गयी अभद्र टिप्पणी से स्पष्ट है कि डा. हरि दत्त नेमी एक बेहद निरंकुश अधिकारी है।

अतः आपसे प्रार्थना है कि जनपद कानपुर नगर के सी.एम.ओ. डा. हरि दत्त नेमी के खिलाफ जांच करवाते हुए दोषी पाये जाने की दशा में कानपुर नगर से स्थानान्तरित करने हेतु संबंधित को निर्देशित करने की कृपा करें।

सादर।

भवदीय

(अभिजीत सिंह सांगा)
विधायक
210, बिठूर, कानपुर नगर

निवास/कार्यालय : 34/7, ॐ भवन, सूबेदार नगर, बिठूर, कानपुर नगर
ईमेल : mlabithoor210@gmail.com

विधायक अभिजीत सिंह सांगा ने सीएमओ के खिलाफ लिखा पत्र

श्री शिव परिवार सेवा समिति द्वारा निकाली झांकियां

अमरनाथ यात्रा में भगवती नगर बेस कैंप जम्मू में भंडारे का आयोजन करती है समिति

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। श्री शिव परिवार सेवा समिति द्वारा शिव बारात गुजैनी एच ब्लाक शिव मंदिर से होते हुए समिति के कार्यालय दरोगा गेस्टहाऊस तक निकली गई।

जिसमें कई झाकियों की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। वहीं पनकी के महामंडलेश्वर कृष्ण दास महंत जी भी शिव परिवार के साथ पैदल चलते आए उन्होंने बताया कि इस भंडारे में कानपुर के लोगो को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए।

श्री शिव परिवार सेवा समिति जो कि अमरनाथ यात्रा में यात्रियों के लिए ज़म्बू बेस कैंप भगवती नगर में चौबीस घंटे निरन्तर भंडारा चलाती है और यह छठवां भंडारा है।

उपाध्यक्ष दुर्गेश तिवारी ने बताया कि कानपुर के सहयोग से ही चलाया जाता है जो कि हमारी संस्था की बहुत बड़ी ताकत बन जाती है, इसमें राशन सामग्री को इकट्ठा करना होता हैं और ट्रक द्वारा भेजा जाता है । वहीं मीडिया प्रभारी धीरज कुमार ने बताया कि जिस किसी को सहयोग देना हो वह हमारे कार्यालय शिव परिवार निकट दरोगा चौराहा बर्रा में दे सकता है। संस्था में मौजूद दीपक गौड़, राजेंद्र भट्ट, बालमीकि गुप्ता, नितिन कुमार, शिवा द्विवेदी राम औतार राजेश शर्मा व अन्य लोग शामिल रहे।

सराफा कारोबारी से रंगदारी मांगने वाला मुठभेड़ में गिरफ्तार पैर में लगी गोली, साथी फरार

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। सराफा कारोबारी से रंगदारी मांगने वाला पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है, जबकि साथी फरार हो गया। बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

कानपुर में गोविंदनगर के सराफा कारोबारी अनिल कुमार गुप्ता पर गोली चलवाकर 50 लाख की रंगदारी मांगने वाले को पुलिस ने मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में बदमाश के पैर में गोली लगी है। पुलिस ने आरोपित के पास से तमंचा भी बरामद किया है। हालांकि कार्रवाई के दौरान आरोपित का साथी नीले रंग की अपाचे बाइक मौके से भागने में कामयाब रहा। पुलिस उसकी तलाश कर रही है।

बता दें कि क्यू ब्लॉक गोविंदनगर निवासी अनिल कुमार गुप्ता की बिल्हौर में सेठ रामकुमार गुप्ता ज्वैलर्स के नाम से दुकान है। आठ जून की रात वह बिल्हौर से घर लौटे, तभी पीछा करते हुए आए अपाचे सवार लुटेरों ने उन पर गोली चलाई थी। हालांकि उन दौरान वह कार की डिग्गी से सामान निकाल रहे थे तो उन्हें सिर्फ धमाका ही सुनाई दिया। उन पर हुए हमले की जानकारी उन्हें तब हुई, जब हमला करवाने ने फोन करके 50 लाख रुपये की रंगदारी मांगी।इसके बाद उन्होंने गोविंदनगर पुलिस से शिकायत दर्ज कराई। जांच में लगी पुलिस टीम ने जिस नंबर से रंगदारी मांगी गई। उसके सिम मालिक को उठाया तो पता चला कि मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान से सिम चोरी हो गया था। पुलिस ने मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले दुकानदार को उठाया, लेकिन कुछ हासिल नहीं हो सका। इसी बीच बदमाश ने एक और अंजान नंबर से कॉल करके रुपयों का इंतजाम होने की बात पूछी, लेकिन वह सिम भी एक मजूदर के नाम पर लिया गया, जो ओडिशा का रहने वाला था।

गुजैनी बायपास के पास हुई मुठभेड़

वह मेट्रो में काम कर रहा था। हालांकि जांच के दौरान पुलिस को शिवराजपुर स्थित टोल प्लाजा से हमलावरों के चेहरों के फुटेज मिल गए, जो बिल्हौर से पीछा करते हुए गोविंद नगर पहुंचे थे। उन्हीं फुटेज और सोमवार को लगातार बदमाश के मोबाइल आन करने पर पुलिस उनकी तलाश कर रही थी।

सम्पादकीय

कामयाबी का जनोत्सव

सरकारी आंकड़ों पर विश्वास करें तो इस महाकुंभ में 66 करोड़ से अधिक तीर्थयात्रियों ने गंगा-यमुना व अदृश्य सरस्वती के संगम पर महाकुंभ के दौरान डुबकी लगायी। एक भगदड़ की घटना में कुछ श्रद्धालुओं का असमय काल-कवलित होना दुखद ही था। कुछ अग्निकांड भी हुए। लेकिन यदि बात करोड़ों श्रद्धालुओं के संगम में स्नान व उनके आने-जाने व रहने की व्यवस्था की हो तो योगी सरकार अपनी पीठ थपथपा सकती है। रूस-अमेरिका जैसी महाशक्तियों की आबादी से अधिक जनसंख्या का प्रबंधन निश्चय ही एक बड़ी चुनौती थी। ऐसे दौर में जब उपभोक्ता संस्कृति सिर चढ़कर बोल रही है, तब सनातन संस्कृति का ऐसा उफान चौंकाता है। जिसमें लोग तमाम कष्ट सहकर संगम में डुबकी लगाने को आतुर दिखे। त्याग-संयम से परिचित कराना कुंभ संस्कृति का उद्देश्य भी रहा है। इस तरह हमने अपने पुरखों की गौरवशाली विरासत का सम्मान किया। जिसमें सदियों से करोड़ों लोग बिना चिट्ठी-पत्री के स्वत-स्फूर्त भाव से कुंभ के मेले में जुटते रहे हैं। भारतीय संस्कृति में ऐसी क्या खासियत है? महाकुंभ जैसे इतने बड़े आयोजन कैसे सफलतापूर्वक होते हैं? यह देखने पूरी दुनिया के जिज्ञासु, विभिन्न धर्मों के अनुयायी, फोटोग्राफर और पत्रकार सदियों से महाकुंभ में जुटते रहे हैं। महाकुंभ के सफल आयोजन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि महाकुंभ ने पूरी दुनिया को युग-परिवर्तन की आहट और विशाल आयोजन की क्षमता से रूबरू कराया है। महत्वपूर्ण यह है कि तीर्थयात्रियों ने जिस तरह दिल खोल कर खर्च किया, वो निश्चय ही उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था का तारणहार बनेगा। बताते हैं कि इससे प्रदेश की जीडीपी में करीब साढ़े चार लाख करोड़ रुपये का इजाफा होगा। जो देश की तमाम देशी-विदेशी इनवेस्ट समिटों से कहीं ज्यादा ठोस आय का स्रोत बना है। कई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इस महाकुंभ के नाम हुए। वीरवार को तीन वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाणपत्र मुख्यमंत्री योगी को सौंपे गए। विपक्ष, खासकर सपा व कांग्रेस कुंभ आयोजन को लेकर हमलावर रहे हैं। वहीं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने महाकुंभ के समापन पर कहा कि ये सरकारी महाकुंभ है। असली कुंभ तो माघ पूर्णिमा को ही संपन्न हो चुका था।इस बार के महाकुंभ को टेक्नोलॉजी के महाकुंभ के रूप में भी याद किया जाएगा। महाकुंभ में विशेष एल्गोरिदम के जरिये इस्तेमाल पांच सौ एआई कैमरे क्राउड डेंसिटी व फैशियल रिकग्निशन के लिये इस्तेमाल किए गए। जिसके जरिये करोड़ों श्रद्धालुओं की गिनती संभव हुई। वहीं बिछुड़ों को परिजनों से मिलाने, आपराधिक गतिविधियों पर अंकुश लगाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। इस बात का वैज्ञानिक अध्ययन होना चाहिए कि भगदड़ को कैसे टाला जाए। आखिर क्यों दो सौ- तीन सौ किलोमीटर के जाम लगते रहे हैं। कैसे ट्रेनों का संचालन बिना किसी व्यवधान के किया जाए। हालांकि, 16 नई ट्रेनें चलाने की बात कही गई, लेकिन तमाम स्टेशनों पर ट्रेन में चढ़ने के लिये मारामारी होती रही है। देश में धार्मिक पर्यटन की अपार संभावनाएं हैं। देश में महाकाल कोरिडोर व काशी कोरिडोर की तर्ज पर चारों कुंभ स्थलों पर संरचना निर्माण की दिशा में सोचा जाना चाहिए। प्रयागराज महाकुंभ से प्रेरित होकर महाराष्ट्र सरकार ने नासिक में 2027 में होने वाले सिंहस्थ कुंभ की तैयारियों की शुरुआत कर दी है। बहरहाल, महाकुंभ को सामाजिक समरसता के उत्सव के रूप में भी याद किया जाएगा, जहां जाति, धर्म, क्षेत्र व भाषा की वर्जनाएं टूटती नजर आई।

यूक्रेन के दुर्लभ खनिज पर अमेरिकी गिद्ध दृष्टि

पुष्परंजन

'सेंटर फॉर यूरोप एशिया स्टडीज' की निदेशक और 'शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स' की सीनियर फेलो थेरेसा फॉलन ने कहा, 'ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय नीति के सभी मानदंडों को तोड़ दिया है, और वह इतना लेन-देन करके अमेरिका की बहुत सी सॉफ्ट पावर खो रहे हैं।' फॉलन ने फिर कहा, 'लेन-देन करना ठीक है, लेकिन यह तो जबरन वसूली है।'शुक्रवार को पूरी दुनिया की निगाहें व्हाइट हाउस में होने वाली एक डील पर होंगी, जिसे एक देश पर थोपा जाना है। अमेरिका जिन देशों को आर्थिक मदद देता है, उसे किस रूप में वसूलता है, यह देखने के लिए भारत के लोग भी तैयार हो जाएं। यूक्रेन की लीडरशिप के लिए आगे कुआं-पीछे खाई वाली स्थिति है। जेलेंस्की पुतिन से बचने के वास्ते अमेरिका से मदद की अपेक्षा कर रहे थे, ट्रंप ने भूखे हिंस्र जंगल के राजा की तरह 'मेमने' को दबोच लिया। ट्रंप ने गुरुवार को पत्रकारों से कहा, 'मैंने सुना है कि वह शुक्रवार को आ रहे हैं। निश्चित रूप से, अगर वह चाहें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। ट्रम्प ने कहा, कि यह डील एक ट्रिलियन डॉलर तक की हो सकती है, इससे अमेरिकी करदाताओं को उनका पैसा वापस मिल जाएगा।'

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को कहा था, कि अमेरिका और यूक्रेन ने महत्वपूर्ण खनिजों के सौदे के मसौदे पर सहमति जताई है, जिसकी कीमत लगभग 1 ट्रिलियन डॉलर हो सकती है। यह सौदा यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की द्वारा पहले के मसौदे को अस्वीकार करने के एक सप्ताह बाद हुआ है। ट्रम्प ने मंगलवार को ओवल ऑफिस में संवाददाताओं से कहा कि ज़ेलेंस्की शुक्रवार को वाशिंगटन आकर एक 'बहुत बड़ी डील' पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं। बुधवार शाम को, ज़ेलेंस्की ने कहा कि यह अमेरिका के साथ सहयोग के लिए एक आर्थिक ढांचा है, जिसमें अभी तक कोई अमेरिकी सुरक्षा गारंटी शामिल नहीं है।

पिछले हफ़्ते ज़ेलेंस्की ने एक पुराने ड्राफ्ट को अस्वीकार कर दिया था, क्योंकि इसमें यूक्रेन के लिए सुरक्षा गारंटी के बारे में विवरण नहीं था। ट्रंप अब भी बदले नहीं हैं। राष्ट्रपति ट्रम्प ने बुधवार को कहा, 'मैं बहुत ज्यादा सुरक्षा गारंटी नहीं देने जा रहा हूं। हम यूरोप से ऐसा करवाने जा रहे हैं।' नोक-झोंक में ट्रम्प ने ज़ेलेंस्की को 'तानाशाह' तक कह डाला था। सोमवार को, ज़ेलेंस्की ने कहा था कि मैं शांति के लिए इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हूं। ज़ेलेंस्की ने मांग की, कि यूक्रेन को अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन (नाटो) की सदस्यता दी जानी चाहिए। लेकिन, वाशिंगटन ने नाटो का सदस्य बनने की मांग को 'अवास्तविक' करार दिया है। अमेरिका की गिद्ध दृष्टि यूक्रेन की दुर्लभ खनिज संपदा पर है।दुर्लभ मृदा खनिज वैश्विक स्तर पर पृथ्वी के गर्भ में पाए जाने वाले 17 भारी धातुओं का एक समूह है। नियोडिमियम, लैंथेनम, सेरियम, प्रेजोडियम, यिट्रियम, टेरबियम और यूरोपियम जैसे कुछ दुर्लभ मृदा तत्वों का उपयोग कंप्यूटर हार्ड ड्राइव, टेलीविज़न, मोबाइल स्क्रीन और कैमरा लेंस जैसे उच्च तकनीक वाले उत्पादों के निर्माण में किया जाता है। वर्तमान में, ऐसे दुर्लभ खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक चीन है, जो दुनिया की आपूर्ति का कम से कम 60 प्रतिशत निकालता है।अमेरिकी भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के अनुसार, 2024 में अमेरिका अपनी 80 प्रतिशत दुर्लभ खनिजों की जरूरतों के लिए चीन, मलेशिया, जापान और एस्टोनिया पर निर्भर था। कीव के साथ दुर्लभ खनिजों का सौदा करने के पीछे की मंशा, अमेरिका को बड़ी तकनीक का अधिकेंद्र बनाना है। अपने अभियान के दौरान, ट्रम्प ने एक अन्य करीबी सहयोगी ताइवान पर अमेरिका के चिप व्यवसाय को चुराने का भी आरोप लगाया था। टैरिफ की धमकियों के बीच, ताइवान ने अमेरिका में निवेश बढ़ाने का वादा किया। इस महीने की शुरुआत में, ट्रम्प ने व्हाइट हाउस में संवाददाताओं से कहा था, कि हम यूक्रेन को वाशिंगटन द्वारा भेजे गए लगभग 375.8 बिलियन डॉलर की वापसी चाहते हैं। कीव को भेजी गई सहायता के बारे में ट्रम्प के अनुमान अमेरिकी सरकार के आंकड़ों के विपरीत हैं। 'यूक्रेन ओवरसाइट' के अनुसार, 30 सितंबर, 2024 तक अमेरिका ने यूक्रेन की सहायता के लिए कुल 183 बिलियन डॉलर भेजे थे, जो यूक्रेन को भेजी गई सहायता को रिकॉर्ड करने के लिए अमेरिकी सरकार द्वारा बनाई गई एक वेबसाइट है।जिस स्टाइल में ट्रंप यह सब कर रहे हैं, उसका दुनिया भर में विरोध होना शुरू हो गया है। 'सेंटर फॉर यूरोप एशिया स्टडीज' की निदेशक और 'शिकागो काउंसिल ऑन ग्लोबल अफेयर्स' की सीनियर फेलो थेरेसा फॉलन ने कहा, 'ऐसा लगता है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा करके अंतर्राष्ट्रीय नीति के सभी मानदंडों को तोड़ दिया है, और वह इतना लेन-देन करके अमेरिका की बहुत सी सॉफ्ट पावर खो रहे हैं।' फॉलन ने फिर कहा, 'लेन-देन करना ठीक है, लेकिन यह तो जबरन वसूली है।'यूक्रेन के पास 34 पदार्थों में से 22 मिनरल्स हैं जिन्हें यूरोपीय संघ 'महत्वपूर्ण कच्चे माल' के रूप में परिभाषित करता है। दुनियाभर में 110 मिलियन टन दुर्लभ खनिज हैं। इसमें से 44 मिलियन टन चीन में हैं, जो दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। इसके अलावा ब्राजील में 22 मिलियन टन, वियतनाम में 21 मिलियन टन, रूस में 10 मिलियन टन, और भारत में 7 मिलियन टन दुर्लभ खनिज का अनुमान है। कोई सुरक्षा गारंटी नहीं, फिर भी जेलेंस्की अमेरिका के साथ समझौते पर हस्ताक्षर कर रहे हैं, क्या यह किसी क़िस्म का ब्लैकमेल है? मॉस्को ने यूक्रेन के बड़े हिस्से पर कब्ज़ा कर रखा है, जिसमें क्रीमिया भी शामिल है, जिसे उसने 2014 में अपने साथ मिला लिया।

समाज में वैज्ञानिक सोच विकसित करना जरूरी

वैज्ञानिक सोच को विकसित करना

डा0 रेनू यादव

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने का अवसर भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम 'विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में भारतीय युवाओं का सशक्तीकरण' रखा गया है।अठाईस फरवरी को भारत में राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिन देश के महान वैज्ञानिक सी.वी. रमन की खोज व रमन प्रभाव को सम्मान देने के लिए मनाया जाता है। जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। यह दिन भविष्य में विज्ञान और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए भी महत्वपूर्ण है।

सन? 1928 की बात है, जब भारतीय वैज्ञानिक चंद्रशेखर वेंकटरमन ने एक अभूतपूर्व खोज की। उन्होंने पाया कि जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम से गुजरता है, तो कुछ फोटॉनों की ऊर्जा में परिवर्तन हो जाता है। इस सिद्धांत को 'रमन प्रभाव' कहा गया और इससे भौतिकी तथा रसायन विज्ञान में क्रांतिकारी परिवर्तन आए। इस खोज ने न केवल स्पेक्ट्रोस्कॉपी में नए द्वार खोले, बल्कि मेडिकल साइंस, विशेष रूप से जांच, दवा निर्माण और नैनो प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी और अंतरिक्ष अनुसंधान में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया।यह खोज भारत के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान हुई, जिससे भारतीय वैज्ञानिकों में आत्मनिर्भरता और आत्मसम्मान की भावना विकसित हुई। इसके कारण भारत में विज्ञान शिक्षा और अनुसंधान को एक नई दिशा मिली। साथ ही, इस उपलब्धि ने लोगों को वैज्ञानिक दृष्टिकोण अपनाने और तर्कसंगत सोच विकसित करने के लिए प्रेरित किया। यही कारण रहा कि इस ऐतिहासिक उपलब्धि को सम्मान देने के लिए 1986 में भारत सरकार ने 28 फरवरी को 'राष्ट्रीय विज्ञान दिवस' के रूप में मनाने की घोषणा की। इसका उद्देश्य विज्ञान को जनजीवन से जोड़ना, आम जनता की भलाई के लिए विज्ञान की भूमिका को समझना और विज्ञान के प्रति रुचि को बढ़ावा देना है।आज विज्ञान का प्रभाव हमारे दैनिक जीवन के हर पहलू में देखा जा सकता है।

स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक्स-रे, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड और रोबोटिक सर्जरी जैसी तकनीकों ने चिकित्सा को अत्याधुनिक बना दिया है। संचार क्रांति के कारण मोबाइल फोन, इंटरनेट, 5जी और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने सूचना के आदान-प्रदान को तेज और प्रभावी बना दिया है। खाद्य उत्पादन के क्षेत्र में जीन संपादन, ड्रोन तकनीक और स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम जैसी वैज्ञानिक उपलब्धियों ने खेती को अधिक टिकाऊ और कुशल बनाया है। परिवहन और अंतरिक्ष विज्ञान में भी भारत ने उल्लेखनीय प्रगति की है। हाल ही में भारत के चंद्रयान-3 और गगनयान मिशन ने अंतरिक्ष में नई संभावनाओं को जन्म दिया। मिशन मंगल और अन्य अंतरिक्ष अभियानों ने भारत को इस क्षेत्र में वैश्विक स्तर पर प्रतिष्ठा दिलाई है।भारत ने विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कई ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल की हैं। डॉ. विक्रम साराभाई, जिन्हें भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम का जनक माना जाता है, ने इसरो की स्थापना की और देश के अंतरिक्ष मिशनों की नींव रखी।

डॉ. होमी भाभा ने भारत के परमाणु कार्यक्रम की दिशा तय की, जबकि डॉ. एम. विश्वेश्वरैया ने इंजीनियरिंग और जल प्रबंधन के क्षेत्र में अमूल्य योगदान दिया। आज इसरो, डीआरडीओ, सीएसआईआर जैसी संस्थाएं भारत को तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बना रही हैं।हालांकि, विज्ञान ने दुनिया को आगे बढ़ाने में मदद की है, लेकिन कुछ चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं।

वैज्ञानिक सोच का अभाव और अंधविश्वास समाज के विकास में बाधा डालते हैं। आज भी लोग बिना वैज्ञानिक आधार के कई धारणाओं को मानते हैं, जिससे समाज में रूढ़िवादिता बनी रहती है। इसे दूर करने के लिए वैज्ञानिक शिक्षा को प्राथमिक स्तर से ही बढ़ावा देने की आवश्यकता है।मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों को सशक्त करने के लिए अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना जरूरी है। इसके अलावा, पर्यावरण और कृषि में विज्ञान के उपयोग को बढ़ाने की आवश्यकता है। बायो-प्लास्टिक, अपशिष्ट प्रबंधन और स्वच्छ ऊर्जा जैसी तकनीकों को अपनाने से न केवल प्रदूषण की समस्या से निपटा जा सकता है, बल्कि जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभावों को रोका जा सकता है। इसी तरह कृषि क्षेत्र में टिकाऊ खेती, जल संरक्षण और जैविक खेती को प्रोत्साहित करके खाद्यान्न और पोषण के संकट से पार पा सकते हैं, जिससे स्वास्थ्य क्षेत्र पर बढ़ते दबाव को भी कम किया जा सकता है।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस केवल वैज्ञानिक उपलब्धियों को याद करने का दिन नहीं, बल्कि बच्चों और युवाओं में वैज्ञानिक सोच को विकसित करने का अवसर भी है। इसी को ध्यान में रखते हुए राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2025 की थीम 'विकसित भारत के लिए विज्ञान और नवाचार में भारतीय युवाओं का सशक्तीकरण' रखा गया है। इस थीम का उद्देश्य भारतीय युवाओं को विज्ञान और नवाचार में नेतृत्वकारी भूमिका निभाने के लिए सक्षम और प्रेरित करना है, ताकि भारत एक विकसित राष्ट्र बन सके।

बिल्हौर के एसके हॉस्पिटल में गर्भवती की संदिग्ध मौत

» हॉस्पिटल संचालक के मुताबिक मरीज पहले से था सीरियस

» महिला डॉक्टर ने पहले ही कहा था कानपुर ले जाइए

» पुलिस सीसीटीवी फुटेज से लगाएगी सच्चाई का पता

मासूम के संग गईं दो जिंदगियां, परिजनों ने हत्या का आरोप लगाकर किया हंगामा

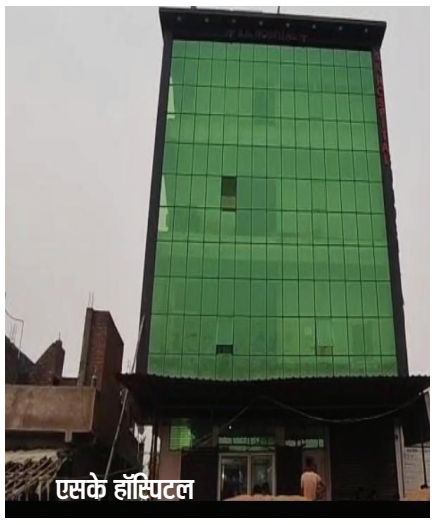
एसके हॉस्पिटल

बवाल कर रहे परिजनों को शांत कराते कोतवाल व एलआईयू इंस्पेक्टर.

घटना की जानकारी देता पति ब्रजेश

स्वराज इंडिया संवाददाता

बिल्हौर (कानपुर)। सोमवार का दिन बीबीपुर गांव के ब्रजेश पर क़यामत बनकर टूटा। उनकी पत्नी रीना जो अपने कोख में एक जिंदगी को जन्म देने के लिए पाल रही थी,वह खुद मौत के आगोश में चली गई। ये हादसा हुआ बिल्हौर के एस के हॉस्पिटल में। जहां इलाज के नाम पर जो हुआ, उस पर सवाल खड़े हो गए हैं। परिजनों का आरोप है कि अस्पताल में इलाज के दौरान डॉक्टरों की लापरवाही ने दो जानें ले लीं। पहले पेट में पल रहे बच्चे की मौत हुई, फिर माँ भी हमेशा के लिए चली गई। रीना की हालत बिगड़ने के बाद उसे कानपुर रेफर कर दिया गया, लेकिन अस्पताल से कानपुर ले जाते समय ही उसने दम तोड़ दिया।

परिजनों का कहना है कि बच्चे की मौत पेट में पहले ही हो चुकी थी, लेकिन उन्हें इसकी भनक तक नहीं लगने दी गई। शाम क़रीब 3 बजे जब रीना की हालत और बिगड़ी, तब आनन-फानन में रेफर किया गया। मगर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही रीना के मौत की ख़बर गांव पहुंची, अस्पताल के बाहर मातम गुस्से में बदल गया। दर्जनों की तादाद में इकट्ठा हुए परिजनों ने हॉस्पिटल पर हत्या का आरोप लगाते हुए जमकर हंगामा किया। बवाल की सूचना पर कोतवाली पुलिस व खुफ़िया विभाग के इंस्पेक्टर मौके पर पहुंच गए। घंटों चले इस विरोध प्रदर्शन में पुलिस ने लोगों को कई बार समझाने का प्रयास किया। वहीं कोतवाल अशोक कुमार सरोज ने ज़ब कार्रवाई का भरोसा दिया तो, परिजनों का गुस्सा ठंडा हुआ। थाना पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर मामले की जांच शुरू कर दी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है।

पुलिस सीसीटीवी फुटेज से सच्चाई का पता लगाएगी

बिल्हौर। बवाल के बाद चर्चाओं में आए एस के हॉस्पिटल में कितने का स्टॉफ और डॉक्टर हैं इसकी जानकारी पुलिस ने जुटाई। साथ ही जच्चा बच्चा की हुई संदिग्ध मौत की सच्चाई का पता लगाने के लिए हॉस्पिटल में लगे सीसीटीवी कैमरे के डीवीआर पुलिस थाने ले गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज चेक कर सच्चाई का पता लगाएगी।

मरीज पहले से ही था सीरियस हॉस्पिटल संचालक

मामले में हॉस्पिटल संचालक से बात की गई तो संचालक ने सारे आरोपों को निराधार बताया। कहा कि मरीज पहले से ही सीरियस था। कानपुर से महिला डॉक्टर जो हॉस्पिटल में मरीजों को देखने व इलाज करने आती हैं उन्होंने मरीज को देखकर इलाज करने से मना कर दिया था और कानपुर रेफर करने की सलाह दी थी।

चार लाख की सुलह की फुसफुसाहट!

बिल्हौर। अस्पताल के बाहर हंगामा कर रहे परिजनों को लेकर अब एक नई चर्चा गर्म है। स्थानीय लोगों का दावा है कि अस्पताल प्रबंधन और परिजनों के बीच करीब चार लाख रुपये में समझौते की बात चल रही है, जिसकी फुसफुसाहट होने लगी है। लेकिन अभी मोहर नहीं लगी है।

हालांकि इस तरह की किसी भी डील की आपका अपना स्वराज इंडिया अख़बार पुष्टि नहीं करता है,लेकिन चर्चा जरुर हो रही है गांव से लेकर तहसील और अस्पताल तक। लेकिन जिस तरह परिजनों के तेवर अचानक बदले और मामला ठंडा पड़ता दिखा,उसने सवाल जरूर खड़े कर दिए हैं। सवाल यह है कि क्या वाकई कुछ देने-लेने की बात हुई...या फिर दुःख की तपिश कुछ देर बाद ठंडी हो गई?

सहकार नगर में सामुदायिक केंद्र की भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिश

»स्थानीय लोगों ने जिलाधिकारी से की कार्रवाई की मांग*

उस्मान कबाड़ी नाम के व्यक्ति ने दी क्षेत्रीय लोगों को जान से मारने की धमकी

स्वराज इंडिया संवाददाता

कानपुर। सहकार नगर, मसवानपुर के स्थानीय निवासियों ने क्षेत्र की एक सार्वजनिक भूमि पर अवैध कब्जे की कोशिशों के खिलाफ जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। यह भूमि शिव कुमारी स्कूल के सामने स्थित है और वर्ष 1971 के लेआउट प्लान में इसे सामुदायिक केंद्र के रूप में सुरक्षित दर्शाया गया था।स्थानीय निवासियों ने आरोप लगाया है कि कुछ भू-माफिया इस सार्वजनिक उपयोग की भूमि पर जबरन कब्जा कर उसे बेचने का प्रयास कर रहे हैं। हालांकि क्षेत्रीय जनता के कड़े विरोध के चलते अब तक वे इसमें सफल नहीं हो पाए हैं।

प्रार्थना पत्र में यह भी बताया गया है कि पहले भी कल्याणपुर थाना क्षेत्र में ऐसे ही एक भू-माफिया के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन उनके गुर्गों द्वारा लगातार कब्जे की कोशिशें की जा रही हैं। साथ ही, स्थानीय लोगों को जान से मारने की धमकियाँ भी दी जा रही हैं।

4 जून को हुए एक घटनाक्रम में भू-माफिया रवि सिंह के गुर्गों, जिनमें एक व्यक्ति उस्मान कबाड़ी बताया गया है — जो कि चोरी की गाड़ियों के अवैध कारोबार से जुड़ा बताया गया है — ने आकर खुलेआम धमकियाँ दीं और अभद्र भाषा का प्रयोग किया। हालांकि, जब स्थानीय निवासियों ने इसका विरोध किया, तो वे मौके से फरार हो गए।

निवासियों ने यह भी आरोप लगाया कि भू-माफिया ने चार स्थानीय लोगों के खिलाफ एक झूठी शिकायत भी थाने में दी, लेकिन जांच में आरोप गलत पाए गए और थानाध्यक्ष ने उन्हें मुक्त कर दिया।

क्षेत्रीय लोगों ने जिलाधिकारी से निम्न तीन मांगें की हैं

1. सामुदायिक केंद्र की भूमि की तत्काल जांच कराई जाए।
2. भू-माफियाओं और उनके गुर्गों पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए।
3. भूमि को सुरक्षित कर वहां सामुदायिक विकास कार्य शीघ्र प्रारंभ किए जाएं।निवासियों ने उम्मीद जताई है कि प्रशासन हस्तक्षेप कर इस सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करेगा और अवैध कब्जाधारियों पर उचित कार्यवाही की जाएगी।

कल्याणपुर के होटलों में बिक रही अस्मत, अब पुलिस की जांच शुरू

» थाना अध्यक्ष बोले सभी चौकियों को निर्देश जारी, जांच के बाद होगी सख्त कार्रवाई

» देह व्यापार पर फोकस में आए होटल, पुलिस की कार्रवाई से दहशत में दलाल

प्रमुख संवाददाता दैनिक स्वराज इंडिया

कानपुर। दैनिक स्वराज इंडिया द्वारा उजागर किए गए कल्याणपुर क्षेत्र के ओयो होटलों में चल रहे संगठित देह व्यापार के गोरखधंधे की खबर पर आखिरकार प्रशासन की नींद टूटी है। जब यह मामला कल्याणपुर थाना अध्यक्ष के संज्ञान में लाया गया, तो उन्होंने इसे गंभीरता से लेते हुए त्वरित प्रतिक्रिया दी। उनका कहना है,थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली सभी पुलिस चौकियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि वे क्षेत्र में संचालित ओयो होटलों की गहन जांच करें।

यदि जांच में किसी भी होटल में अनैतिक गतिविधियाँ पाई जाती हैं तो न सिर्फ होटल संचालक, बल्कि इसमें संलिप्त कर्मचारियों, मैनेजर, दलाल और अन्य लोगों पर भी सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।थाना अध्यक्ष के इस बयान से संकेत मिलता है कि अब तक जिन मामलों को नजरअंदाज किया जा रहा था, उन्हें प्राथमिकता दी जा रही है। यह बयान पुलिस की गंभीरता को दर्शाता है, लेकिन यह भी देखना बाकी है कि क्या कार्रवाई ज़मीनी स्तर पर प्रभावशाली होगी या सिर्फ कागजों तक सीमित रहेगी।

होटलों में बढ़ी हलचल, दलालों में मचा हड़कंप

जैसे ही थाना अध्यक्ष की ओर से जांच के आदेश जारी हुए, कल्याणपुर क्षेत्र में संचालित कई ओयो होटलों में हलचल और बेचैनी देखी जा रही है। सूत्रों के अनुसार, कुछ होटलों में अचानक बुकिंग कैंसिल का सिलसिला शुरू हो गया है। कई युवतियां और महिलाएं जो रोज़ाना होटल में देखी जाती थीं, वे पिछले दो दिनों से नदारद हैं। होटल स्टाफ ने बुकिंग रजिस्टर, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल चैट जैसी सूचनाएं भी हटानी शुरू कर दी हैं, ताकि जांच में कुछ भी हाथ न लगे।

स्थानीय नागरिकों का कहना है कि पिछले कुछ महीनों में इन होटलों में रोज़ाना दर्जनों गाड़ियां आती-जाती थीं और कई बार संदिग्ध गतिविधियों को लेकर सवाल भी उठाए गए थे,

लेकिन पुलिस प्रशासन मौन रहा। अब जब पुलिस कार्रवाई की बात सामने आई है, तो लोगों में उम्मीद जगी है कि शायद इस बार कुछ ठोस कदम उठाए जाएंगे।

हालांकि, क्षेत्र में यह भी चर्चा है कि यदि जांच निष्पक्ष और गहराई से हुई, तो इस पूरे गोरखधंधे के पीछे खड़े कई रसूखदार लोगों के चेहरे भी उजागर हो सकते हैं। साथ ही पुलिस और प्रशासनिक तंत्र में बैठे कुछ लोगों की मिलीभगत की परतें भी खुल सकती हैं, जो अब तक इस अनैतिक कारोबार को संरक्षण देते रहे हैं।

आईआईटी छोड़ बना खेतों का चैंपियन, रचा सफलता का अध्याय

» बिना सरकारी मदद के खड़ा किया मॉडल फार्म, 500 से अधिक मजदूरों को दे रहे रोजगार

» पक्की सड़क के लिए लगा रहे गुहार, मगर सरकारी तंत्र अब तक मौन

स्वराज इंडिया न्यूज़ ब्यूरो

कानपुर देहात। मलासा ब्लॉक के प्रगतिशील किसान राहुल सिंह ने जब सब कुछ छोड़ खेती को अपनाया, तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह युवक हजारों के लिए प्रेरणा बन जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी ऑनर्स करने के बाद राहुल को एनआईटी कालीकट में दाखिला मिला, लेकिन स्वास्थ्य कारणों से पढ़ाई अधूरी छोड़नी पड़ी। गांव लौटकर उन्होंने खेती को कैरियर बनाया। परिवार के विरोध के बावजूद खीरा, लौकी, टमाटर, बैगन जैसी सब्जियों की खेती शुरू की। आधुनिक तकनीक जैसे मल्च विधि और स्केटिंग सिस्टम अपनाकर लागत घटाई और उत्पादन बढ़ाया।

आज वे 12 बीघा ज़मीन पर खेती कर रहे हैं और 500 से अधिक मजदूरों को रोजगार दे रहे हैं। एक बीघा खीरे की खेती में 35,000 की लागत पर लाखों की आमदनी कर रहे हैं।

उनके खेत अब क्षेत्र में 'मॉडल फार्म' बन गए हैं, जहां आसपास के किसान भी आकर प्रशिक्षण लेते हैं।

सरकारी योजनाएं सिर्फ कागजों में, जमीनी हकीकत से जूझता मेहनती किसान

राहुल सिंह का दर्द ये है कि तमाम योजनाओं के बावजूद उन्हें आज तक न तो कोई सरकारी अनुदान मिला, न ही बुनियादी सुविधाएं।

उन्होंने बताया कि उनके खेतों तक पहुंचने के लिए आज भी कच्ची सड़क है। बारिश के मौसम में खेत तक आना-जाना, खाद-पानी या फसल मंडी तक पहुंचाना बेहद कठिन हो जाता है। कई बार अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन नतीजा शून्य है।

राहुल कहते हैं, सरकार किसानों के लिए बड़ी-बड़ी योजनाओं की घोषणा करती है, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और है। जो किसान असल में कुछ कर रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पूछता। ऐसे किसान की उपेक्षा सरकारी तंत्र की असफलता को उजागर करती है।

अब देखने वाली बात यह होगी कि क्या मेहनती किसान की आवाज़ सुनी जाएगी या यह आवाज़ भी अन्य किसानों की तरह फाइलों में दबी रह जाएगी।

महिला आयोग की उपाध्यक्ष का औचक निरीक्षण, दी सख्त हिदायते

» वृद्धाश्रम में महिलाओं से संवाद, अस्पताल में नवजात बच्चियों को दी बेबी केयर किट

» महिला बंदीगृह में व्यवस्था सुधार के दिए निर्देश, वन स्टॉप सेंटर की कार्यशैली पर पूछे सवाल

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष (उपमंत्री स्तर) अपर्णा यादव ने कानपुर देहात में विभिन्न महिला संबंधित संस्थानों का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण की शुरुआत वृद्धाश्रम से हुई, जहां उन्होंने वृद्ध महिलाओं से संवाद कर हालचाल जाना और उन्हें पेंशन से संबंधित प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए। मौके पर फल की टोकरी, कोल्ड ड्रिंक आदि वितरित किए गए।

इसके पश्चात जिला महिला चिकित्सालय में निरीक्षण किया गया, जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत कन्या जन्मोत्सव कार्यक्रम मनाया गया। उपाध्यक्ष ने नवजात 21 बालिकाओं की माताओं को बेबी केयर किट वितरित कर उनके मनोबल को बढ़ाया। अस्पताल के एस एन सी यू, आई सी यू, ओ पी डी सहित अन्य वार्डों की व्यवस्थाएं देखी गईं।

महिला बंदीगृह और वन स्टॉप सेंटर पर विशेष फोकस

अपर्णा यादव ने वन स्टॉप सेंटर का भी निरीक्षण किया, जहां अल्पावास में रह रही एक बालिका से मुलाकात कर उसकी स्थिति की जानकारी ली। केस रजिस्टर, शेल्टर रजिस्टर सहित कर्मचारियों की कार्यशैली पर जानकारी ली गई।जिला महिला बंदीगृह के निरीक्षण में महिला बंदियों से संवाद किया गया। परिसर की साफ-सफाई और मूलभूत सुविधाओं की समीक्षा के बाद जेल अधीक्षक को निर्देश दिए गए कि महिला बंदियों को भोजन पकाने में शामिल किया जाए और उन्हें ब्रेड बनाने का प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराया जाए।

इस अवसर पर मुख्य चिकित्सा अधीक्षक वंदना सिंह, जिला प्रोबेशन अधिकारी रेनू यादव, समाज कल्याण अधिकारी गीता सिंह, जेल अधीक्षक धीरज सिन्हा, जेलर, डिप्टी जेलर, और महिला कल्याण से जुड़े अन्य अधिकारी मौजूद रहे।

7 साल बाद शिक्षकों को मिला तबादले का मौका

जिले के अंदर स्वैच्छिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू, 25 से 29 जून तक ऑनलाइन आवेदन

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। सात साल के लंबे इंतजार के बाद परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को जिले के अंदर स्वैच्छिक स्थानांतरण का अवसर मिला है। बेसिक शिक्षा परिषद ने इस संबंध में आदेश जारी करते हुए समायोजन प्रक्रिया की समय सारिणी भी घोषित कर दी है। शिक्षक 25 से 29 जून के बीच ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे, जिसकी छायाप्रति 30 जून तक जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) कार्यालय में जमा करनी होगी। इसके बाद बीएसए द्वारा आवेदन का सत्यापन और डाटा लॉक की प्रक्रिया 30 जून से 1 जुलाई के बीच पूरी की जाएगी। 3 जुलाई को स्थानांतरण सूची जारी की जाएगी और उसी दिन संबंधित शिक्षकों को कार्यमुक्त भी कर दिया जाएगा।

इस प्रक्रिया के तहत केवल वे शिक्षक पात्र होंगे जो मानक से अधिक संख्या में अध्यापक वाले विद्यालयों में कार्यरत हैं, जिन्हें सरप्लस श्रेणी में रखा गया है। इन शिक्षकों को आवश्यकता वाले विद्यालयों में समायोजित किया जाएगा, जिनकी सूची 20 से 24 जून के बीच पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। शिक्षक अधिकतम 10 विद्यालयों के विकल्प दे सकेंगे, लेकिन कम से कम एक विकल्प देना अनिवार्य होगा। यदि कोई शिक्षक विकल्प नहीं देता है, तो उसका आवेदन स्वतः निरस्त मान लिया जाएगा।

स्थानांतरण वरीयता जनपद में नियुक्ति की तिथि के आधार पर तय की जाएगी। यदि दो शिक्षकों की नियुक्ति तिथि समान है, तो अधिक आयु वाले शिक्षक को प्राथमिकता मिलेगी। वहीं आयु भी समान होने पर अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम को आधार बनाया जाएगा। यू-डायस पोर्टल पर दर्ज छात्र संख्या के आधार पर छात्र-शिक्षक अनुपात के अनुसार जिन विद्यालयों में अध्यापकों की आवश्यकता होगी, उन्हें चिह्नित कर सूची में दर्शाया जाएगा।

शिक्षकों की यह मांग वर्षों से लंबित थी। अब जब उन्हें अंत:जनपदीय स्तर पर स्वैच्छिक तबादले का अवसर मिला है, तो शिक्षा विभाग में काफी उत्साह और संतोष का माहौल है।

स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक सपना देवी द्वारा हर्षिता प्रिंटर्स 127/875, साकेत नगर, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से मुद्रित व 119/13, दर्शनपुरवा, कानपुर नगर- 208012 (उप्र) से प्रकाशित। संपादक: अनूप कुमार RNI No.: UPHIN/2023/86769 | Email: swarajindia2023@gmail.com | Mob: 7800009853, | Website: www.swarajindianews.com | (समस्त वाद-विवाद कानपुर न्यायालय के अधीन होंगे)

एसपी की भी नहीं सुनती मंगलपुर थाने की पुलिस !

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर देहात। मंगलपुर इंस्पेक्टर और संदलपुर चौकी इंचार्ज का मनमान रवैया सामने आया है। एसपी के निर्देश के बाद भी मारपीट की रिपोर्ट दर्ज नहीं की। एसपी ने जिन पीड़ित महिलाओं को थाने भेजा था। वहां कई घंटे बैठाने के बाद बिना रिपोर्ट दर्ज किए भगा दिया गया। ये तो जांच में ही स्पष्ट हो सकेगा कि खाकी पर खद्दर का दबाव है या फिर कानून को कठपुतली बनाने के लिए दबंगों से हाथ मिला चुके हैं इंस्पेक्टर। फिलहाल विवादित जमीन पर निर्माण का विरोध करने पहुंची महिलाओं को लाठी डंडों से पीटने वाले मुंछों में ताव दे रहे हैं। वजह है कि पीटने के बाद उन्होंने मनमानी एफआईआर भी दर्ज करा दी है। कानून का पालन कराने की शपथ लेने वाले केवल कठपुतली की तरह नांच रहे हैं।

यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भ्रष्टाचार और कानून व्यवस्था के भले ही तमाम दावे करें

» संदलपुर की विवादित जमीन प्रकरण में एसपी ने दूसरे पक्ष का भी मुकदमा लिखने निर्देश दिए थे

» एसपी ने जिन पीड़ित महिलाओं को थाने भेजा था। वहां कई घंटे बैठाने के बाद बिना रिपोर्ट दर्ज किए भगा दिया गया

लेकिनह्य जमीनी हकीकत बेहद अलग है। कानून के रक्षक सबसे पहले रसूखदार लोगों के साथ खड़े नजर आते हैं। ऐसा ही मामला सिकंदरा तहसील के संदलपुर कस्बा का सामने आया है। यहां ग्राम समाज की विवादित जमीन पर निर्माण को लेकर तनाव चल रहा है। 12 जून को विवादित जमीन पर निर्माण कार्य का विरोध करने के लिए जितेंद्र संखवार उसकी मां सुखरानी व पत्नी पहुंची। पुलिस की सरपस्ती में निर्माण कराने वाले दबंगों ने लाठी डंडों से

सच्चाई के दम पर जोश के साथ...
RNI No: UPHIN/2023/86769
www.swarajindianews.com
swarajindia2023@gmail.com swarajindianews swarajindianews
मूल्य: ₹ 02
स्वराज इंडिया
सांध्यकालीन समाचार पत्र
ईरान में सुरक्षित जगहों पर पहुंचाए जा रहे हैं भारतीय स्टूडेंट » Pg 12
कानपुर, सोमवार, 16 जून, 2025
वर्ष: 02, अंक: 166, पृष्ठ: 8+4
इनसाइड सीएमओ साहब तो बड़े वाले निकले... » Pg03

संदलपुर में बन रहे मड़ौली जैसे हालात!

कानपुर देहात : ग्राम सभा की बेशकीमती विवादित जमीन पर किसी भी वक्त हो सकता खूनी संघर्ष

» मुख्य संवाददाता, स्वराज इंडिया

कानपुर देहात। मंगलपुर थाना क्षेत्र के संदलपुर गांव में जमीन के एक टुकड़े के लिए कागजी जंग अब खूनी संघर्ष की ओर बढ़ रही है। हालात मड़ौली कांड जैसे बनते जा रहे हैं। विवादित जमीन पर निर्माण कराने में पुलिस बढ़चढ़ कर भूमिका निभा रही है। स्थिति ये है कि विवादित जमीन में निर्माण का विरोध करने पर आरोपियों ने लाठी डंडों से महिलाओं को पीटा गया और खास बात देखिए कि मार खाने के बाद भी महिलाओं की रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई। इसकी वजह है कि दूसरा पक्ष रसूखदार और पूर्व प्रधान है। ऐसे में पुलिस पीड़ितों के साथ अपराधियों जैसा सलूक कर रही है। जिससे कि कानून व्यवस्था सवालों के घेरे में खडी हो गई है।

सिकंदरा तहसील क्षेत्र के संदलपुर कस्बा में ब्लाक के पास बेशकीमती जमीन पर पूर्व प्रधान की पहले से नजर थी। गांव के लालाराम ने बताया कि उक्त जमीन पर पुश्तैनी कब्जा है उसमें गुमटी रखकर परिवार का भरण पोषण करता था। वर्ष 2017 में तत्कालीन प्रधान शाइना बेगम ने अपने देवर उवैश अहमद व परिवार के लोगों को पट्टा कर दिया था। नियमानुसार पट्टा गरीब और जरूरतमंद को होना चाहिए। प्रधान ने अपने देवरों को पट्टा किया उनके पास लाइसेंसी असलहे और पक्के मकान है। इसके बाद भी आवासी पट्टा दिया गया। मामले की शिकायत पर तत्कालीन डीएम के निर्देश पर तत्कालीन एसडीएम ने जांच की थी। जांच में पट्टा अवैध पाया गया था। मामला आयुक्त कानपुर की कोर्ट में चल रहा है। पुलिस व राजस्व कर्मियों की सांठगांठ से पूर्व प्रधान विवादित ग्राम समाज की जमीन पर निर्माण करा रहा है। पुलिस कोई बात सुनने को तैयार नहीं है।

कठघरे में इंस्पेक्टर मंगलपुर की कार्रवाई

संदलपुर में ब्लाक के पास विवादित जमीन में निर्माण के विरोध पर लाठी डंडों से महिलाओं की खुलेआम पिटाई की थी। वहीं महिलाओं के साथ गए युवक जितेंद्र कुमार उर्फबबलू ने पेट्रोल डालकर आत्मदाह की कोशिश की थी। मामले में पुलिस ने जितेंद्र, कबीरूलहसन समेत पांच लोगों पर रिपोर्ट दर्ज कर ली जबकि पीड़ित पक्ष मार खाने के बाद भी अफसरों के यहां चक्कर काट रहा है। वीडियो और मेडिकल लिए पीड़ित पक्ष अफसरों को दिखाता घूम रहा है। मंगलपुर प्रभारी निरीक्षक खुलेआम आरोपियों के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। उनकी एक पक्षीय कार्रवाई उन्हें कठघरे में खड़ा कर रही है।

जानिए क्या था मड़ौली कांड

ग्राम सभा की जमीन में निर्माण और कब्जे को लेकर दो पक्षों के बीच लंबे समय तक विवाद चलता रहा। इसके बाद कब्जा हटाने गई टीम के सामने मां बेटी की झोपड़ी के अंदर जलकर मौत हो गई थी। मामले में पुलिस और राजस्व विभाग की भूमिका निष्पक्ष न होने से इतनी बड़ी घटना हुई थी। अगर समय रहते मजबूत कदम उठा लिए जाते तो मड़ौली कांड नहीं होता। अब ये ही हालात संदलपुर में है। वहां भी पुलिस और राजस्व विभाग के अफसरों की भूमिका ठीक नहीं है।

उनकी पिटाई शुरु कर दी। मारपीट का वीडियो बनाने वाले एक दुकानदार का दंबग मोबाइल भी छीन ले गए। महिलाओं को पीटे जाने का वीडियो वायरल होने के बाद जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े होने लगे। पीड़ित महिलाएं एसपी के चौखट के कई दिनों तक चक्कर काटतीं रहीं। मामला एसपी के संज्ञान में आया तो उन्होंने इंस्पेक्टर मंगलपुर को रिपोर्ट दर्ज करने के निर्देश दिए। साथ ही पीड़ित महिलाओं को थाने भेजा। मंगलवार को महिलाएं थाने पहुंची तो उन्हें कई घंटे बैठाए रखा गया। इसके बाद रिपोर्ट न लिखे जाने की बात कहकर भगा दिया गया। इस संबंध में डेरापुर सीओ राजीव सिरोही को कई बार कॉल किए गए बात नहीं हो सकी। इस मामले में मंगलपुर एसएचओ ने बताया कि दोनों पक्षों पर हमारी नजर है, जो उचित होगा उसे पर कार्रवाई की जाएगी। अपर जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार कार्य हो रहा है लेकिन अगर दूसरा पक्ष अपने अभिलेख पेश करता है तो कार्य नहीं होने दिया जाएगा। वही चौकी इंचार्ज को कार्वाई करने के लिए निर्देशित किया गया है।

कोरोना काल से बंद लखनऊ गोंडा पैसेंजर चलाने की मांग

» लखनऊ गोंडा पैसेंजर के संचालन से क्षेत्र के आम जनों गरीबों व छात्र-छात्राओं को लखनऊ गोंडा सहित तमाम जगहों पर जाने में मिलेगी सहूलियत

स्वराज इंडिया संवाददाता

बाराबंकी। कोरोना काल से बंद पड़ी लखनऊ गोंडा पैसेंजर के न चलने से आमजनों व गरीबों को सफर के लिए भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनों तथा जनप्रतिनिधियों की केंद्र सरकार व रेल मंत्री से पुनः पैसेंजर चलने की मांग का कोई असर नहीं दिख रहा है इससे लोगों में रोष व्याप्त है।

ज्ञात हो कि पूर्व में लखनऊ गोंडा पैसेंजर के संचालन से क्षेत्र के आम जनों गरीबों व छात्र-छात्राओं को लखनऊ गोंडा सहित तमाम जगहों पर आने जाने के लिए सस्ते किराए में आवागमन की अच्छी सुविधा

मिलती थी और पैसेंजर ट्रेन के आवागमन से बुढ़वल स्टेशन गुलजार रहता था तमाम गरीब बेरोजगार लोग चाय समोसा आदि का व्यवसाय करके अपने परिवार का भरण पोषण भी करते थे। आज वह सभी लोग बेरोजगार हो गए हैं यही नहीं लोधेश्वर महादेवा कोटवा धाम आदि मेले वर्ष में कई बार लगते हैं जिसमे लाखो की संख्या में श्रद्धालुओं का आवागमन पैसेंजर के माध्यम से होता था कोरोना काल से इस ट्रेन के बंद हो जाने के चलते सफर के लिए गरीबों की जेबों पर डाका पड़ता है। बहुत ही कम पैसे में लखनऊ गोंडा बाराबंकी सहित तमाम स्थान की यात्रा हो जाती थी आज लोगों को बस व प्राइवेट वाहनों का सहारा लेकर मंहगा किराया देना पड़ता है। गौरतला बात यह है कि मेलों में तमाम ऑटो व टेंपो चालको की भक्तों को लाने ले जाने में काफी कमाई होती थी वह भी बंद हो गई है इस पैसेंजर ट्रेन के संचालन नहीं होने के चलते लोधेश्वर महादेवा कोटवा धाम व बांसा शरीफ में श्रद्धालुओं की संख्या में भी काफी कमी आई है। रेलवे विभाग के द्वारा मेमो ट्रेन भी चलाने की कई बार आश्वासन दिया गया है लेकिन आज तक संचालन नहीं हो पाया है यदि मेमो ट्रेन का संचालन हो जाता तो बंद पड़ी पैसेंजर ट्रेन की कुछ हद तक भरपाई हो जाती।

बसपा सुप्रीमो मायावती के दरबार में जुटे बसपा के दिग्गज नेता

» मिशन 2027 की रणनीति पर हुआ मंथन

» पंचायत चुनाव पर भी की गई विस्तृत चर्चा

» विधायकी का ताल ठोक रहे दावेदार बसपा सुप्रीमो से मिले

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ/कानपुर। बहुजन समाज पार्टी (बसपा) के केंद्रीय कार्यालय में सोमवार को पार्टी की शीर्ष नेता और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के आवास पर बड़ी हलचल देखी गई। पार्टी के कई दिग्गज नेता,वरिष्ठ पदाधिकारी और कई जिलों के जिलाध्यक्ष लखनऊ स्थित कार्यालय में एकत्र हुए।

विश्वस्त सूत्रों के मुताबिक यह बैठक आगामी विधानसभा चुनाव 2027 एवं नगर निकाय चुनाव को लेकर बसपा की रणनीतिक तैयारियों के तहत बुलाई गई थी। बहन मायावती ने बारी बारी से सभी से व्यक्तिगत मुलाकात की और क्षेत्रीय समीकरणों पर फीडबैक लिया।

बैठक के दौरान संगठनात्मक ढांचे में संभावित फेरबदल, बूथ स्तर पर मजबूती एवं युवाओ को 50 फीसदी भागीदारी देने के साथ साथ सोशल इंजीनियरिंग पर ज़ोर दिए जाने की चर्चाएं ज़ोरों पर रहीं।

राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस बैठक से साफ है कि बसपा अब मैदान में उतरने को तैयार है और मायावती एक बार फिर सक्रिय राजनीति में पूरी ताक़त से वापसी का संकेत दे रही हैं। हालांकि बैठक समाप्ति के बाद कोई भी नेता मीडिया से खुलकर नहीं बोला।लेकिन चर्चा जरुर करता दिखा कि बसपा पार्टी फिर से वापसी कर रही है।

विधायकी की ताल ठोक रहे दावेदारों ने आशीर्वाद लिया

बिल्हौर। आगामी विधानसभा चुनाव में विधायकी में ताल ठोकने वाले दावेदार अभी से ही चुनावी तैयारी में जुट गए हैं। और सोमवार बसपा सुप्रीमो से आशीर्वाद लेने भी पहुँचे । वहीं कानपुर की बिल्हौर विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे बिल्हौर निवासी एडवोकेट विनय गौतम कानपुर जिलाध्यक्ष व पूर्व सांसद, मुख्य मंडल प्रभारी कानपुर लखनऊ मुनकाद अली के साथ बहन मायावती के आवास में दाखिल हुए। और उन्होंने बसपा सुप्रीमो के सामने चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। विनय कुमार गौतम ने बताया कि बहन जी के सामने अपनी बात रखी है। उन्होंने आशीर्वाद दिया है। जिसके बाद वह अभी से ही तैयारी में जुट गए हैं।

सरप्लस अध्यापकों का जिले के अंदर होगा स्वैच्छिक समायोजन

» शिक्षकों को मिला जिले के अंदर सामान्य तबादले का अवसर

» 7 साल बाद शिक्षकों की मुराद होगी पूरी

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

कानपुर। परिषदीय स्कूलों के शिक्षकों को स्वेच्छा से जिले के अंदर (अंतःजनपदीय) स्थानांतरण/समायोजन करवाने के लिए आदेश जारी किया गया है हालांकि इन शिक्षकों को सात साल (2017 के) बाद जिले के अंदर सामान्य तबादले का अवसर मिलेगा। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन करने का समय 25 जून से 29 जून यानी 5 दिन दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति बीएसए कार्यालय में 30 जून तक जमा करनी होगी। 3 जुलाई को साफ्टवेयर के माध्यम से स्थानांतरण सूची जारी की जाएगी और इसी दिन शिक्षकों को कार्यमुक्त भी किया जायेगा। परिषद सचिव सुरेन्द्र कुमार तिवारी ने इसके लिए समय सारिणी जारी कर दी है।

स्वेच्छा से जिले के अंदर स्थानांतरण किए जाने की मांग शिक्षक कई वर्षों से कर रहे थे। आदेश के अनुसार मानक से अधिक अध्यापक वाले प्रत्येक विद्यालय के सरप्लस शिक्षकों की संख्या व अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालय में रिक्ति पदों की संख्या पोर्टल पर ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। विद्यालय में आवश्यकता से अधिक कार्यरत शिक्षक स्वेच्छा से अध्यापक की आवश्यकता वाले अधिकतम 10 विद्यालयों का विकल्प दे सकेंगे। पोर्टल पर प्रदर्शित विद्यालयों में से कम से कम एक विकल्प दिया जाना अनिवार्य होगा। विकल्प नहीं भरने वालों का आवेदन स्वतः निरस्त माना जाएगा। इसमें शिक्षक-छात्र का अनुपात मानक के अनुरूप रहने तक स्थानांतरण किए जाएंगे। साफ्टवेयर के माध्यम से कार्यरत जनपद में वरिष्ठता (जनपद में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से) के आधार पर वरीयता क्रम में दिए अध्यापक की आवश्यकता वाले विद्यालयों के विकल्पों के आधार पर स्थानांतरण किए जाएंगे। शिक्षकों के आवेदन बीएसए सत्यापित करेंगे। जनपद में नियुक्ति की तिथि समान होने की दशा में अधिक आयु वाले शिक्षक को वरीयता दी जाएगी तथा आयु भी समान होने पर शिक्षक के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम में लाभ दिया जाएगा। छात्र संख्या के आधार पर नियमानुसार छात्र-शिक्षक अनुपात की गणना करते हुए शिक्षक की आवश्यकता वाले विद्यालयों को चिह्नित कर 20 से 24 जून तक सूची ऑनलाइन प्रदर्शित की जाएगी। इसी के अनुरूप शिक्षक आवेदन कर सकेंगे। शिक्षक एवं शिक्षिकाओं द्वारा ऑनलाइन आवेदन 25 जून से 29 जून तक किया जायेगा। ऑनलाइन आवेदन की छायाप्रति सम्बन्धित जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय में 30 जून को जमा करनी होगी। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों द्वारा ऑनलाइन सत्यापन एवं डाटा लॉक किए जाने की कार्यवाही 30 जून से 1 जुलाई तक की जाएगी। 3 जुलाई को स्थानांतरण सूची निर्गत की जाएगी और उसी दिन शिक्षकों को कार्यमुक्त कर दिया जाएगा।

बॉम्बे हॉस्पिटल
नियर आघू रोड, कानपुर-आगरा हाईवे, अकबरपुर, कानपुर देहात

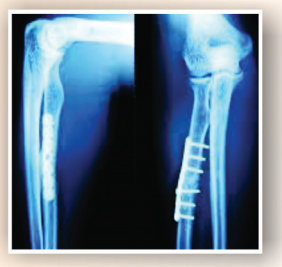

24 घंटे इमरजेंसी सुविधा
24 घंटे एम्बुलेंस व मेडिकल स्टोर की सुविधा
दूरबीन विधि द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन
हेल्पलाइन नं.: 8355017999, 8858997333

हड्डी के सभी ऑपरेशन, गुर्दे की पथरी
पित्ताशय की पथरी, फिशर, नासूर
अपेन्डिक्स, प्रोस्टेट, कैंसर की गांठ, भगंदर
हर्निया, हाइड्रोसील, छाती का कैंसर
पेट की चोट व अन्य समस्याएं
बच्चेदानी व अण्डाशय की गांठ
घुटने का प्रत्यारोपण, पाइल्स (बवासीर)

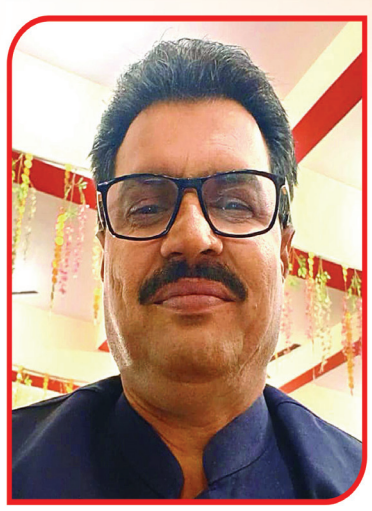

डॉ. सुरेश यादव
डायरेक्टर

....अयोध्या जिला अस्पताल में खून के सौदागर....

अयोध्या जिला अस्पताल के ब्लड बैंक में खून की दलाली

» यहां खून मुफ्त नहीं, कीमत लेकर मिलता है

» सरकारी ब्लड बैंक बना ब्लड माफियाओं का अड्डा

» सीसीटीवी में कैद एप्रेनधारी की काली करतूत

स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

अयोध्या। यह अस्पताल है या कोई मंडी? जहां जिंदगी के बदले बोली लगती है, और जहां मरीज का खून बहने से पहले उसका परिजन खून के लिए खून पसीना बहाता है–वो भी सात हजार रुपये में!मवई की एक महिला प्रसूता थी। जिला महिला चिकित्सालय में भर्ती थी। शरीर में खून की भारी कमी थी। सरकारी कागजों में उसे प्राथमिकता से मुफ्त रक्त मिलना था, लेकिन जमीनी हकीकत अलग थी–यहां खून मुफ्त नहीं, कीमत लेकर मिलता है। और कीमत भी ऐसी कि गरीब की रीढ़ टूट

जाए- सात हज़ार रुपये!

परिजन अरविंद कुमार ब्लड बैंक पहुंचे तो जवाब मिला डोनर लाओ।जब कोई डोनर नहीं मिला, तो बाहर एक 卐सफेद एप्रैनधारी卐 मिला, जिसने खुद को अस्पताल कर्मी जैसा दर्शाया और कहा- 卐खून चाहिए? सात हज़ार दो, अभी देता हूं! क्यूआर कोड स्कैन हुआ, खून का सौदा तय हुआ और कुछ ही मिनटों में रक्त की बोतल हाज़रि!

स्वराज इंडिया कहता है

ये मामला महज़ एक दलाल का नहीं। यह एक संवेदनशील तंत्र की सुन्न नसों में दौड़ता अपराध है। जांच होनी चाहिए मगर फाइलों में नहीं, जनता के बीच और न्याय के सामने। वरना अगली बार हो सकता है, खून के लिए ऑक्शन हो और बोली लगे दस हजार, बीस हजार, पचास हजार... और किसी की माँ की जान उस बोली में हार जाए!

स्वराज इंडिया का सवाल ये है कि

-इतनी जल्दी दुर्लभ ए+ ब्लड कहां से आया?
- किसकी मिलीभगत से यह खेल हो रहा है?
-और सरकारी ब्लड बैंक किसकी जागीर बन गया है?
एप्रैन वाला कौन? डॉक्टर, कंपाउंडर या दलाल?
ब्लड बेचने वाला आरोपी कोई आम राहगीर नहीं था। व्हाट्सएप डीपी में एप्रैन पहना है।

अस्पताल के अंदर घूमता है। मरीजों को पहचानता है, उनके तीमारदारों से भाव-ताव करता है। ये खूनी दलाल कौन है? क्या यह ब्लड बैंक की मिलीभगत से खेला गया रैकेट है?

सीएमओ का छापा - मगर दलाल गायब!

सूचना सीएमओ तक पहुंची। वो खुद टीम लेकर महिला अस्पताल पहुंचे। तीमारदार से बात की।

ब्लड बैंक गए। सीसीटीवी खंगाले। मगर दलाल नदारद। पहचान तो हो गई है, पर अब वो अस्पताल में नहीं, सिस्टम में छुपा है।

पुराना खेल, नया चेहरा - ब्लड माफिया फिर सक्रिय

पहले भी ऐसे आरोप लगे है। शिकायते हुईं। जांचें हुईं। और हुआ क्या? फाइलें बंद, दलाल एक्टिव।

स्वास्थ्य विभाग की शुरुआती जांच बताती है कि ब्लड बेचने वाला गिरोह फिर सक्रिय हो गया है। अस्पताल के कर्मचारी आंखें मूंदे हैं या फिर जेबें गर्म कर रहे हैं।

सरकारी अस्पताल या दलाली का दरबार?

जब सरकारी अस्पताल में एप्रैनधारी दलाल घूमे, सीसीटीवी में कैद हों और ब्लड की बोतलें कीमत तय होने पर ही बाहर निकलें तो जनता पूछेगी ही-

-क्या ब्लड बैंक अब सरकारी नहीं रहा?
- क्या मानवता की कीमत सात हजार तय हो गई है?
-और क्या अब अस्पताल ब्लड मार्केट बन चुका है?

दुनिया के लिये खतरनाक हो सकती है इजरायल-ईरान जंग

अभी तक दोनों देश प्रॉक्सी वार तक सीमित थे, पहली बार प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति

» संजय सक्सेना, स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। 13 जून 2025 को 'ऑपरेशन राइजिंग लायन' के तहत इजरायल ने ईरान के कई परमाणु और सैन्य ठिकानों पर एक बड़ा हमला किया। इन हमलों में नतांज़ जैसे प्रमुख परमाणु संस्थानों, मिसाइल अड्डों और सैन्य कमांड सेंटर्स को निशाना बनाया गया। हमले में 200 से अधिक लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हुए। इजरायल का दावा है कि यह कार्रवाई ईरान की परमाणु क्षमता को रोकने के लिए आवश्यक थी। इसके जवाब में ईरान ने मिसाइलों और ड्रोन के जरिए इजरायल के कुछ क्षेत्रों पर हमला किया, हालांकि इनमें से अधिकांश हमले इजरायल और अमेरिका की वायु रक्षा प्रणालियों द्वारा निष्क्रिय कर दिए गए।

यह पहला अवसर है जब दोनों देश प्रत्यक्ष युद्ध की स्थिति में आ गए हैं। पहले के वर्षों में दोनों देश प्रॉक्सी लड़ाइयों तक सीमित थे, जैसे सीरिया, लेबनान और गाजा पट्टी के जरिए, लेकिन अब सीधा टकराव शुरू हो गया है। इससे मध्य-पूर्व में पहले से अस्थिर माहौल और अधिक जटिल हो गया है। अमेरिका ने इजरायल को सैन्य सहायता प्रदान की है और यह संकेत दिया है कि यदि संघर्ष बढ़ता है तो वह और अधिक समर्थन देगा। हालांकि, अमेरिका के अंदर इस मुद्दे पर मतभेद हैं। कुछ वर्ग संघर्ष को जल्द समाप्त करने के पक्ष में हैं, जबकि अन्य सतर्क रणनीति अपनाने की सलाह दे रहे हैं।

इजरायल के अनुसार, उसका लक्ष्य ईरान की परमाणु क्षमता को समाप्त करना है, जबकि ईरान का दावा है कि वह आत्मरक्षा कर रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ईरान अभी तक परमाणु हथियार बनाने का अंतिम निर्णय नहीं ले चुका है, लेकिन उसका कार्यक्रम तेजी से उस दिशा में बढ़ रहा है। इससे परमाणु युद्ध का खतरा भी बढ़ता जा रहा है।

ईरान की प्रतिक्रिया में उसके प्रॉक्सी नेटवर्क का प्रयोग भी संभावित है। हिज़्बुल्लाह, हूथी विद्रोही और इराकी मिलिशिया जैसे समूहों को ईरान सक्रिय कर सकता है। इससे पूरे मध्य-पूर्व में लड़ाई के कई मोर्चे खुल सकते हैं। खासकर यदि हिज़्बुल्लाह इजरायल के खिलाफ सक्रिय हुआ, तो लेबनान सीमा पर भी युद्ध भड़क सकता है।

इस स्थिति में इजरायल को दो-तरफा मोर्चा संभालना पड़ सकता है। तेल और गैस की आपूर्ति पर इस युद्ध का बड़ा असर पड़ सकता है। ईरान होमुज़्ज़ जलसंधि के ज़रिए विश्व के लगभग 20 कच्चे तेल का मार्ग नियंत्रित करता है। यदि यह बाधित होता है तो वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम कीमतों में तेज उछाल आ सकता है। भारत जैसे देश, जो ऊर्जा आयात पर निर्भर हैं, उन्हें आर्थिक झटका लग सकता है। इसके साथ-साथ वैश्विक आपूर्ति श्रृंखलाएं भी प्रभावित होंगी, जिससे महंगाई बढ़ सकती है।संघर्ष के मानवीय पहलू भी गंभीर हैं। मिसाइल हमलों से नागरिकों की मौत हो रही है, लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हो रहे हैं और विस्थापन की आशंका बढ़ रही है। यदि युद्ध लंबा खिंचता है तो शरणार्थी संकट उत्पन्न हो सकता है, जिससे यूरोप और एशिया के देशों पर अतिरिक्त दबाव पड़ेगा।

इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने इस हमले को यहूदी अस्तित्व की रक्षा के लिए आवश्यक बताया है। उन्होंने कहा है कि अगर अब कार्रवाई नहीं की गई, तो भविष्य में परमाणु हमले की आशंका बनी रहेगी। वहीं, ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला खामनेई ने चेतावनी दी है कि उनका देश अपने दुश्मनों को करारा जवाब देगा। यह बयानों की भाषा इस बात की ओर संकेत करती है कि संघर्ष अभी खत्म नहीं हुआ है और आगे और तीव्र हो सकता है।

कई देशों ने हालात शांत करने की अपील

अंतरराष्ट्रीय समुदाय की ओर से युद्ध को रोकने के प्रयास किए जा रहे हैं। अमेरिका, यूरोप, रूस और चीन ने कूटनीतिक माध्यमों से हालात शांत करने की अपील की है। ओमान में कुछ गुप्त वार्ताएं भी चल रही हैं, लेकिन इजरायल के आक्रामक कदमों और ईरान की प्रतिक्रिया से इनका सफल होना संदिग्ध है। भारत के लिए यह संघर्ष विशेष महत्व रखता है। एक ओर यह देश की ऊर्जा सुरक्षा को प्रभावित कर सकता है, वहीं खाड़ी क्षेत्र में बसे लाखों भारतीयों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ सकती है। इसके अतिरिक्त वैश्विक व्यापार और आर्थिक स्थिरता पर भी इसका असर हो सकता है।

विनाशकारी हो सकता युद्ध का परिणाम

अगर यह युद्ध नियंत्रित नहीं किया गया, तो यह पूरे मध्य-पूर्व को चपेट में ले सकता है और संभव है कि यह तीसरे विश्व युद्ध जैसी भयावह स्थिति की ओर बढ़े। इसलिए वैश्विक कूटनीति, संयम और त्वरित हस्तक्षेप अत्यंत आवश्यक है। संक्षेप में, ईरान और इजरायल के बीच वर्तमान युद्ध सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, बल्कि यह एक संभावित वैश्विक संकट की भूमिका है। इसमें न केवल क्षेत्रीय अस्थिरता, बल्कि आर्थिक संकट, मानवीय त्रासदी और परमाणु खतरे का भी सम्मिलन है। यदि यह समय रहते नहीं रुका, तो इसके परिणाम पूरी दुनिया के लिए विनाशकारी हो सकते हैं।

प्रेमी संग पकड़ी गई पत्नी

पुलिस और पति को देख होटल की छत से लगा दी छलांग

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

बागपत। बागपत के बड़ौत शहर कोतवाली क्षेत्र में एक मामला उस समय चर्चा में आ गया, जब एक विवाहिता होटल की छत से छलांग लगाकर फरार हो गई, वजह थी विवाहेतर संबंध। महिला अपने प्रेमी के साथ होटल में मौजूद थी और पुलिस को पति के साथ आते देख डर गई। वह तुरंत होटल की खिड़की से कूदी और फरार हो गई।

जानकारी के मुताबिक, महिला और उसका पति का पहले से कानूनी विवाद चल रहा है। मंगलवार को पति को सूचना मिली कि उसकी पत्नी बड़ौत स्थित एक होटल में अपने प्रेमी के साथ रुकी हुई है। पति ने तुरंत डायल 112 पर कॉल कर पुलिस को सूचना दी। जब पुलिस पति के साथ होटल पहुंची, तो महिला ने पति और पुलिस को साथ देखते ही पकड़े जाने के डर से होटल की छत से लगभग 12 फीट की ऊंचाई से छलांग लगा दी।

ये पूरी घटना वहां मौजूद ससुराल पक्ष के किसी व्यक्ति ने मोबाइल कैमरे में कैद कर ली। वीडियो में महिला को छत से कूदते हुए साफ देखा जा सकता है।

वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हुआ वायरल : वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिससे देखकर क्षेत्रवासी भी हैरान रह गए। हालांकि, पुलिस ने इस मामले में अभी तक कोई अधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। पति-पत्नी के बीच पहले से चल रहे कानूनी विवाद की जांच के साथ अब यह नया मामला भी जुड़ गया है।

यूपी में 504 ग्राम पंचायत कम 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। राज्य सरकार ने ग्राम पंचायतों के पुनर्गठन की अधिसूचना जारी कर दी है, जिसके तहत प्रदेश में अब 504 ग्राम पंचायतों की संख्या घटा दी गई है। नई व्यवस्था के अनुसार, अब कुल 57,695 ग्राम पंचायतों में चुनाव कराए जाएंगे। पंचायती राज विभाग ने साफ किया है कि ग्राम पंचायतों की संख्या में अब कोई और बदलाव नहीं किया जाएगा।

पुनर्गठन से बदलेगा प्रशासनिक नक्शा : यह आंशिक पुनर्गठन ग्राम पंचायतों की क्षेत्रीय और प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक तर्कसंगत बनाने के उद्देश्य से किया गया है। छोटी पंचायतों को मिलाकर बड़ी और सशक्त इकाइयां बनाई गई हैं ताकि शासन-प्रशासन को अधिक सक्षम और प्रभावी बनाया जा सके। इससे विकास कार्यों की निगरानी और संसाधनों के उपयोग में भी सुगमता आएगी।

पंचायती राज विभाग ने अगले वर्ष अप्रैल 2026 में पंचायत चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। इस चुनाव में सिर्फ ग्राम प्रधान ही नहीं, बल्कि 826 ब्लॉक प्रमुख और 75 जिला पंचायत अध्यक्ष भी चुने जाएंगे। इन चुनावों को ग्रामीण विकास और नेतृत्व की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

पंचायती राज विभाग ने सभी जिलों के प्रशासन को निदेज़्श दिया है कि वे चुनावी तैयारियों को समयबद्ध तरीके से पूरा करें।

ये हैं यूपी के टॉप 10 आईएएस

योगी सरकार की डैशबोर्ड रैंकिंग में छाए रहे तेज तर्रार अफसर

» स्वराज इंडिया न्यूज ब्यूरो

लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार ने अप्रैल 2025 के लिए सीएम डैशबोर्ड की नवीनतम रैंकिंग जारी की है। इसमें यूपी के टॉप 10 आईएएस अधिकारियों की लिस्ट जारी की गई, जो जनसेवा में समर्पण के लिए टॉप पर रहे हैं। इसमें महराजगंज के जिलाधिकारी संतोष कुमार शर्मा टॉप पर रहे हैं। वहीं, इस लिस्ट में आईएएस राजेश कुमार पांडेय, आईएएस दुर्गा शक्ति नागपाल समेत कई नाम शामिल हैं। यह रैंकिंग जनसुनवाई, कानून-व्यवस्था, जनकल्याणकारी योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन, राजस्व सुधार और समग्र विकास कार्यों के आधार पर तैयार की गई है.

महराजगंज के डीएम पहले स्थान पर : टॉप 10 जिलाधिकारियों (डीएम) की सूची में महाराजगंज के डीएम संतोष कुमार शर्मा ने 9.63 अंकों के साथ पहला स्थान हासिल किया है। जबकि अयोध्या दूसरे और जालौन तीसरे स्थान पर रहा। यह रैंकिंग राज्य सरकार द्वारा शुरू किए गए सीएम डैशबोर्ड के माध्यम से तय की गई है, जो जिलों के प्रदर्शन का आकलन करने का एक प्रभावी डिजिटल उपकरण है।

टॉप 10 जिलाधिकारी और उनके जिले

- **महराजगंज :** संतोष कुमार शर्मा
- **जालौन :** राजेश कुमार पांडेय
- **लखीमपुर खीरी :** दुर्गा शक्ति नागपाल
- **बरेली :** अविनाश सिंह
- **शाहजहांपुर :** धर्मेंद्र प्रताप सिंह
- **श्रावस्ती :** अजय कुमार द्विवेदी
- **कुशीनगर :** महेंद्र सिंह तंवर
- **ललितपुर :** अक्षय त्रिपाठी
- **हरदोई :** अनुनय झा
- **मुजफ्फरनगर :** उमेश मिश्रा